घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com **अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 252- सोमवार 13- जुलाई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये** RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

संक्षिप्त समाचार

हिसार में स्वीट शॉप की लिफ्ट में फंसा वर्कर..जोरदार झटके से गर्दन कटकर धड़ से हुई अलग

हिसार,12 जुलाई 2026। हरियाणा के हिसार से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां राजगुरु मार्केट स्थित एक मशहूर स्वीट शॉप की लिफ्ट में फंसकर एक वर्कर की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि लिफ्ट में झटका लगते ही युवक की गर्दन धड़ से अलग हो गई। इस खौफनाक घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान खुम्बा खेड़ा गांव निवासी जसबीर के रूप में हुई है,जो कल्पना स्वीट्स में हलवाई का काम करता था। जानकारी के मुताबिक,सुबह करीब 6 बजे जसबीर दुकान का कुछ सामान लेने के लिए लिफ्ट से दूसरी मंजिल पर जा रहा था। इसी दौरान उसकी गर्दन अचानक लिफ्ट के दरवाजों के बीच आ गई। लिफ्ट के ऊपर जाते ही एक जोरदार झटका लगा और जसबीर की गर्दन कटकर लिफ्ट की तारों पर जा गिरी,जबकि उसका धड़ लिफ्ट के अंदर ही उल्टा पड़ा रह गया। मौके से सामने आई तस्वीरों में मंजर बेहद विचलित करने वाला है। घटना की दर्दनाक खबर मिलते ही जसबीर के परिजन बदहवास हालत में मौके पर पहुंच गए। इस दिल दहला देने वाले हादसे को लेकर जसबीर के पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके बेटे के साथ यह महज हादसा नहीं है, बल्कि दुकान में उसकी हत्या की गई है। उन्होंने प्रशासन से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में ले लिया।

छुट्टी पर आए आर्मी जवान और पिता की गोली मारकर हत्या,इलाके में हड़कंप

बिहार,12 जुलाई 2026। बिहार के वैशाली जिले से एक अत्यंत दुखद और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां रविवार की सुबह आपसी रंजिश के चलते पिता और पुत्र की निर्मम हत्या कर दी गई। यह सनसनीखेज वारदात बिदुपुर थाना क्षेत्र के रजासो गांव में घटी है। मृतकों की पहचान 60 वर्षीय मुनारिक राय और उनके 35 वर्षीय पुत्र जीतेंद्र कुमार के रूप में हुई है। जीतेंद्र भारतीय सेना (आर्मी) में कार्यरत थे और कुछ दिन पहले ही छुट्टी लेकर अपने घर आए थे। रविवार की सुबह हुई इस दोहरी हत्या ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। प्रारंभिक जांच और ग्रामीणों के बयानों के अनुसार,यह पूरी वारदात वर्षों से चले आ रहे जमीनी विवाद और आपसी रंजिश का परिणाम है। आरोप है कि मुनारिक राय के भतीजे ने ही अपने चाचा और चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या की है। बताया जा रहा है कि रास्ते और जमीन के बंटवारे को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही थी। रविवार की सुबह आरोपी अचानक घर पर पहुंचा और बिना किसी चेतावनी के ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुए इस हमले से संभलने का मौका तक नहीं मिला और मुनारिक राय तथा जीतेंद्र कुमार को गोलियां लग गईं। गंभीर रूप से घायल दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी और उसके साथी मौके से फरार होने में सफल रहे। डबल मर्डर की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक समेत जिले के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है।

दवाओं का असर भी बेअसर,क्या फिर डराने लगा है कोरोना वायरस?

नई दिल्ली,12 जुलाई 2026। कड़प्पा जिले से एक बेहद डराने वाली और आंखें खोलने वाली खबर सामने आई है। यहां कोरोना संक्रमण के कारण एक 46 वर्षीय व्यक्ति की अचानक मौत हो गई। यह घटना इस बात का साफ संकेत है कि महामारी का खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि मरीज को लगातार 4 दिनों तक एंटीबायोटिक दवाओं का हैवी डोज दिया गया था। इसके बावजूद मरीज के लक्षणों में कोई सुधार नहीं हुआ और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। चिकित्सकों के अनुसार यह एक बेहद संक्रामक बीमारी है जो मुख्य रूप से हवा के माध्यम से फैलती है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके मुंह से निकले बारीक कण हवा में तैरने लगते हैं। इसके बाद कम हवा वाले या बंद कमरों में ये कण कई घंटों तक बने रह सकते हैं। यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति इस दूषित हवा में सांस लेता है तो वह भी तुरंत इसकी चपेट में आ जाता है। यही वजह है कि अचानक कोरोना के नए मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह सतर्क हो गया है।

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से

19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक,सरकार रखेगी विधायी एजेंडा...

नई दिल्ली,12 जुलाई 2026। संसद के मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। बैठक में सरकार अपने विधायी एजेंडे की रूपरेखा रखेगी,वहीं विपक्षी दल उन मुद्दों को सामने रखेंगे जिन्हें वे सत्र के दौरान संसद में उठाना चाहते हैं।

मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण विधेयक लाए जाने की संभावना है। सरकार इस सत्र में अपने विधायी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की तैयारी में है,जबकि विपक्ष भी विभिन्न राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। हर संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की परंपरा रही है। इस बैठक का उद्देश्य संसद के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने,सदन में उठने वाले प्रमुख विषयों पर राजनीतिक दलों की राय जानने और सरकार व विपक्ष के बीच संवाद

कायम करना होता है। इस बार मानसून सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना जताई जा रही है। विपक्ष नीट-यूजी पेपर लीक प्रकरण, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े मुद्दों और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की टिप्पणी को सदन में उठा सकता है। कांग्रेस की ओर से रक्षा मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस दिए जाने की बात भी सामने आई है। इसके अलावा कुछ विपक्षी दलों के भीतर हाल के दिनों में दिखी असहमति और राजनीतिक हलचल का असर भी सत्र के दौरान दिखाई दे सकता है।

तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों की सीटिंग व्यवस्था में संभावित बदलाव पर भी राजनीतिक नजरें रहेंगी। सरकार के लिए यह सत्र विधायी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है,क्योंकि कई अहम बिलों को आगे बढ़ाने की तैयारी है। वहीं विपक्ष महंगाई, रोजगार, परीक्षा प्रणाली, राष्ट्रीय सुरक्षा और संघीय ढांचे से जुड़े विषयों पर सरकार से जवाब मांग सकता है। सर्वदलीय बैठक के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मानसून सत्र में किन विधेयकों को प्राथमिकता दी जाएगी और विपक्ष किन मुद्दों पर सरकार से विस्तृत चर्चा की मांग करेगा। ऐसे में 19 जुलाई की बैठक को आगामी संसदीय टकराव और सहयोग दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राजस्थान के डूंगरपुर जिले में एनीकट में डूबने से चार बच्चों की मौत

डूंगरपुर,12 जुलाई 2026। जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के बड़ी गांव स्थित वात्रक एनीकट (तालाब) में रविवार सुबह नहाने गए छह बच्चों में से चार की डूबने से मौत हो गई, जबकि दो बच्चों को समय रहते ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मृतकों में एक ही परिवार के तीन सगे भाई-बहन और उनकी फुफेरी बहन शामिल हैं। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस के अनुसार रविवार सुबह करीब 10 बजे बड़ी गांव निवासी किसान बाबूसिंह डामोर के तीनों बच्चे हिना (24), प्रतीक (20) और इशिता (15) अपनी फुफेरी बहन रौनक (20) पुत्री गौतम भाई परमार निवासी पालनपुर (गुजरात) तथा दो अन्य बच्चों राजवीर और जयसिंह के साथ वात्रक एनीकट में नहाने गए थे। नहाते समय पानी की गहराई का अनुमान नहीं लगने से सभी बच्चे डूबने लगे।

कश्मीर में 60 मिनट के भीतर दो बार फटा बादल

अनंतनाग में बाढ़ से तबाही,होटल और घर जलमग्न

श्रीनगर,12 जुलाई 2026। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में रात महज 60 मिनट के भीतर बादल फटने की दो घटनाओं ने व्यापक तबाही मचा दी। पहलगाम और शांगस (शंगुस) क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ से होटल,रिसॉर्ट,घर और खेत पानी व मलबे की चपेट में आ गए। कई स्थानों पर भूस्खलन भी हुआ, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और पर्यटन गतिविधियों पर भी असर पड़ा। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक किसी जनहानि की सूचना नहीं मिली है। पहली घटना शंगुस के चटरगुल के ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र में हुई,जहां बादल फटने के बाद आरिपथ नाले का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। पहाड़ों से आए तेज बहाव के साथ भारी मात्रा में कीचड़, चट्टानें और पेड़ों का मलबा नीचे बस्तियों और खेतों तक पहुंच गया। इससे सेब के बागों और अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया। इसके लगभग एक घंटे के भीतर दूसरी घटना पहलगाम स्थित ओवेरा वन्यजीव

अभयारण्य क्षेत्र में हुई। यहां ओवेरा नाले में अचानक आई बाढ़ का पानी आधा दर्जन से अधिक होटलों, रिसॉर्ट्स और स्थानीय लोगों के घरों में घुस गया। अचानक आए सैलाब से पर्यटकों और स्थानीय निवासियों में अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद जिला प्रशासन ने राहत एवं बचाव अभियान तेज कर दिया। प्रभावित क्षेत्रों में आपदा राहत दल,पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें तैनात कर दी गई हैं। कई स्थानों पर जमा मलबा हटाने का कार्य जारी है,जबकि बाढ़ग्रस्त इलाकों से पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाज पर हमला...

10 भारतीय सुरक्षित,1 लापता,भारत ने की निंदा

नई दिल्ली,12 जुलाई 2026। भारत ने ओमान के तट के पास होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाज जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इस जहाज के चालक दल में 11 भारतीय सदस्य थे। भारत ने 10 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि एक अभी भी लापता है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ओमान स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है और बचाव अभियान में ओमानी अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा, ओमान के तट पर जहाज जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की निंदा करते हैं। सवार 11 भारतीय नागरिकों में से 10 को बचा लिया गया, जबकि एक लापता है। हम ओमानी अधिकारियों को उनकी मदद के लिए धन्यवाद देते हैं। इस क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले चिंता की बात हैं। हम तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत की अपनी मांग दोहराते हैं, ताकि शांति और स्थिरता लौट

सके। अमेरिका ने तीसरी बार ईरान पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने होर्मुज से गुजर रहे इस जहाज को निशाना बनाया। हमले में साइप्रस के झंडे वाले इस जहाज को भारी नुकसान पहुंचा और इंजन रूम में आग लग गई। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (यूकेएमटीओ) के अनुसार,जहाज के चालक दल ने जहाज छोड़कर लाइफबोट में शरण ली थी। इसी घटना में अब एक भारतीय लापता बताया जा रहा है। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने घोषणा की कि होर्मुज जलडमरूमध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया गया है। वहीं, जहाज पर हमले को लेकर ईरान ने कहा कि ये जहाज अनधिकृत रास्ते से होकर गुजर रहा था। ईरान ने कहा कि कई जहाजों ने बार-बार दी गई चेतावनियों और अधिकृत रास्ते से आगे बढ़ने के निर्देशों को नजरअंदाज किया था।

इसके बाद एक चेतावनी शॉट के तहत जहाजों को रोका गया। अमेरिका ने कहा कि उसने ईरान में 140 ठिकानों को निशाना बनाया है। कम से कम 5 शहरों में अहम रणनीतिक और सैन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं। इसके जवाब में ईरान ने कतर, कुवैत,बहरीन,संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। इन नए हमलों के बाद युद्धविराम लगभग खत्म हो गया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि एकतरफा समझौते अब नहीं माने जाएंगे।

ईरान का बड़ा ऐलान....होर्मुज स्ट्रेट फिर बंद

अमेरिकी दखल खत्म होने तक जहाजों पर रोक

नई दिल्ली,12 जुलाई 2026। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक,'होर्मुज स्ट्रेट' को तत्काल प्रभाव से अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का चौंकाने वाला ऐलान किया है। यह कठोर निर्णय एक समुद्री घटना के बाद लिया गया है, जिसमें ईरान का आरोप है कि एक जहाज ने 'बिना मंजूरी वाले मार्ग' का उपयोग करके इस रणनीतिक क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की थी। इस घटना के बाद IRGC नेवी ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अगले आदेश तक इस जलमार्ग से किसी भी जहाज के गुजरने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

चेतावनी के बाद कार्रवाई: अमेरिका पर साधा निशाना

इस बड़े कदम के पीछे ईरान ने सुरक्षा का हवाला दिया है। IRGC के आधिकारिक बयान के अनुसार, समुद्री

वैश्विक व्यापार पर मंडराया संकट तेल आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण 'चोक पॉइंट्स' में से एक है। वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा इसी संकीर्ण जलमार्ग से होकर गुजरता है। ईरान द्वारा इस रास्ते को बंद करने से वैश्विक ऊर्जा बाजारों में हलचल तेज हो गई है। अगर यह नाकेबंदी लंबी खिंचती है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आना तय है, जिसका सीधा असर भारत सहित दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। शिपिंग कंपनियों ने भी इस मार्ग से बचने के लिए सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है,जिससे माल ढुलाई की लागत बढ़ने का खतरा उत्पन्न हो गया है।

सीमा का उल्लंघन करने वाले जहाज को रोकने के लिए चेतावनी के तौर पर गोलियां भी चलाई गईं। ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिका को इस तनाव का जिम्मेदार ठहराया है। ईरानी सेना ने कहा है कि जब तक इस क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का 'अनावश्यक दखल' बंद नहीं हो जाता, तब तक होर्मुज स्ट्रेट का उपयोग किसी भी व्यापारिक या सैन्य जहाज के लिए नहीं किया जाएगा।

ईरान का यह दावा भू-राजनीतिक अस्थिरता को एक नए स्तर पर ले गया है। ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रहा वाकयुद्ध अब एक प्रत्यक्ष समुद्री संकट में बदलता दिख रहा है। IRGC की इस घोषणा के बाद मध्य-पूर्व में सैन्य तनाव अपने चरम पर है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस मुद्दे पर बेहद चिंतित है क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा को लेकर कोई स्पष्ट गारंटी नहीं दी गई है।

दिग्गज गायिका एस. जानकी नहीं रहीं,पीएम मोदी बोले...

संगीत जगत की अपूरणीय क्षति

नई दिल्ली,12 जुलाई 2026। भारतीय संगीत जगत के एक सुनहरे युग का अंत हो गया है। 'दक्षिण की कोकिला' के नाम से दुनिया भर में मशहूर और देश की महान पार्श्व गायिका एस. जानकी अम्मा का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कर्नाटक के मैसूर स्थित एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से फिल्म उद्योग और संगीत प्रेमियों में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगीत जगत की इस अपूरणीय क्षति पर गहरा दुख प्रकट किया है और इसे भारतीय संस्कृति के लिए एक बड़ा

नुकसान बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर शोक व्यक्त करते हुए जानकी अम्मा को नमन किया। उन्होंने लिखा कि एस. जानकी अम्मा का जाना संगीत और संस्कृति की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। विभिन्न भारतीय भाषाओं में गाए गए उनके जादुई गीत कई पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में गूंजते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपनी मधुर और भावपूर्ण आवाज से हर मानवीय भावना को जीवंत कर दिया, और उनकी गायकी आने वाले लंबे समय तक संगीत प्रेमियों को प्रेरित करती रहेगी। पीएम ने उनके शोक संतप्त परिवार और देश-विदेश में फैले करोड़ों प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। एस. जानकी भारतीय सिनेमा की उन चुनिंदा और महानतम गायिकाओं में शुमार थीं, जिन्होंने अपनी आवाज से भाषाई सीमाओं को तोड़ दिया।

छत्तीसगढ़ के कांकेर सीमा पर नक्सली डम्प से हथियार व नक्सल सामग्री बरामद

नक्सली डम्प से दो .303 रायफल समेत हथियार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले

कांकेर,12 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कांकेर-नारायणपुर सीमा पर आलपरस और गुमचुर के बीच जंगल-पहाड़ी इलाके में सुरक्षा बलों ने संयुक्त सर्चिंग अभियान के दौरान नक्सलियों का एक डंप बरामद किया। डंप से दो .303 रायफल, 32 राउंड कारतूस, लैपटॉप, टैबलेट, वायरलेस उपकरण, नक्सली वर्दी और अन्य सामग्री जब्त की गई। इसकी पुष्टि कांकेर के पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने की है। पुलिस के अनुसार, जिले के संवेदनशील और नक्सल प्रभावित रहे सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार संयुक्त अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए डम्प को बरामद किया। बरामद नक्सली डंप से दो .303 रायफल, 32 राउंड .303 कारतूस, एक लैपटॉप, एक टैबलेट, तीन वायरलेस

बैटरी, एक रेडियो सेट, दो नक्सली वर्दी, पांच पाउच, दो चार्जर, एक बैटरी, नक्सली साहित्य तथा अन्य उपयोगी सामग्री शामिल है। इस संयुक्त अभियान का नेतृत्व बीएसएफ 40वीं वाहिनी के एसी अंकुश कुमार, थाना प्रभारी कोयलीबेड़ा निरीक्षक निर्मल जांगड़े, बीएसएफ इंस्पेक्टर अनुज कुमार,उप निरीक्षक नवीन प्रकाश,उप निरीक्षक सौरभ यादव तथा डीआरजी टीम कमांडर सहायक उप निरीक्षक नरेंद्र नेताम ने किया। कांकेर पुलिस ने बताया कि नक्सल प्रभावित रहे सीमावर्ती क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से आने वाले दिनों में भी सघन सर्चिंग अभियान निरंतर जारी रहेगा।

खूंटाघाट बांध के चौकीदार की पीट-पीटकर हत्या

बिलासपुर,12 जुलाई 2026। रतनपुर थाना क्षेत्र के खूंटाघाट बांध में चौकीदारी करने वाले एक युवक की कथित तौर पर पुरानी रंजिश के चलते पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, मेलनाडीह निवासी श्याम सिंह पोर्ते (40) ने 12 जुलाई को थाना रतनपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह और तीरथ राम यादव खूंटाघाट बांध में चौकीदार के रूप में कार्यरत हैं। शिकायत के मुताबिक, गोलू धीवर और अनिश धीवर पूर्व में बांध से लगातार मछली चोरी करते थे। चोरी का विरोध करने और वीडियो बनाने पर उन्होंने तीरथ राम यादव का मोबाइल फोन तोड़ दिया था। इस मामले में दोनों के विरुद्ध पहले भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा चुकी थी, जिसके बाद से वे तीरथ राम यादव से रंजिश रखते थे।

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के कई डंप

बरामद,सोना,नकदी,हथियार और विस्फोटक जब्त

दंतेवाड़ा,12 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों ने आत्मसमर्पित नक्सलियों की निशानदेही पर बारसूर थाना क्षेत्र के तोड़मा गांव के जंगल-पहाड़ी इलाके में छिपाकर रखे गए नक्सलियों के कई डंप बरामद किए हैं। कार्रवाई में 116 ग्राम सोना, दो लाख रुपये नकद, आधुनिक हथियार,बड़ी मात्रा में गोला-बारूद,विस्फोटक और अन्य नक्सली सामग्री जब्त की गई है। बरामद सामग्री का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 18 लाख रुपये बताया गया है। दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक गौरव राय ओ इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अभियान की निगरानी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कुमार बर्मन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नक्सल ऑप्स) जितेंद्र कुमार खूंटे ने की। पुलिस के अनुसार, हाल ही में आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटे नक्सलियों ने सुरक्षाबलों को नक्सलियों के गुप्त डंप की सटीक जानकारी दी थी। इसके आधार पर संयुक्त टीमों ने तोड़मा के घने जंगलों में सर्च अभियान चलाया, जहां जमीन के नीचे अलग-अलग स्थानों पर छिपाकर रखे गए हथियार, विस्फोटक और अन्य सामग्री बरामद की गई। बरामद सामग्री में -116 ग्राम सोने का बिस्कुट (अनुमानित कीमत 16 लाख),2 लाख नकद, 1

इंसास राइफल एवं 16 इंसास मैगजीन,4 एके-47 मैगजीन और 68 राउंड,23 एसएलआर मैगजीन एवं 34 राउंड,5 बारह बोर बंदूकें और 7 कारतूस,3 बीजीएल लॉन्चर एवं 1 बीजीएल सेल,2 कार्बाइन मैगजीन, 303 के 8 राउंड एवं 45 चार्जर,10 भरमार बंदूकें (टूटी-फूटी),1 रिवॉल्वर,1 एयरगन,6 टिफिन बम, 4 पाइप बम,122 तीर बम,1 पैरा बम,2 देशी हैंड ग्रेनेड,2 देशी मोर्टार,जिलेटिन,20 डेटोनेटर,कोडेक्स वायर का बंडल और 14 कुकर बम, नक्सली वर्दी का कपड़ा, दवाइयां,पर्चे-पाम्पलेट एवं अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई। दंतेवाड़ा पुलिस ने कहा कि आत्मसमर्पित माओवादियों द्वारा दी गई सूचना से यह स्पष्ट है कि वे हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास और शांति की राह पर लौट चुके हैं।

संपादकीय

बरसात में बेहाल होते शहर

एल नीनो के असर के बावजूद मानसून ने देश के हर कोने में दस्तक दे दी है। इससे किसान कुछ हद तक राहत महसूस कर रहे हैं, फिर भी कई क्षेत्रों में बारिश की कमी के कारण फसल की बोआई देरी से चल रही है। फिलहाल यह नहीं कहा जा सकता कि आगे मानसून अपनी गति बरकरार रखेगा और पर्याप्त बारिश होगी।

इस कारण खेती को लेकर चिंता बरकरार है और सरकार भी इसे लेकर सजग दिख रही है। मानसून के आगमन ने जहां भारत के अनेक हिस्सों में भीषण गर्मी से राहत दी है,वहीं हर वर्ष की तरह उसने नगर निकायों की पोल खोल दी है, क्योंकि देश के अनेक छोटे-बड़े शहर वर्षा जनित समस्याओं और खासकर जल भराव से त्रस्त हैं। यह कोई नई बात नहीं।दशकों से भारत के शहरों में लोग बरसात में जल भराव और उससे जुड़ी समस्याओं से जूझते हैं। इसके बाद भी नगर निकायों के काम करने के तौर-तरीके बदल नहीं रहे हैं।

हमारे नगर निकाय न तो जल भराव से निपट पा रहे हैं और न ही सीवर, नालियों और नालों को उफनने से रोक पा रहे हैं। इसी कारण बरसात होते ही जल भराव के कारण कई तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। कहीं ट्रैफिक जाम हो जाता है, कहीं सड़कें धंस जाती हैं, कहीं करेंट उतर आता है तो कहीं लोग गड्ढों में भरे पानी या खुले मैनहोल में गिर जाते हैं।

हर बारिश में न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। बीते दिनों अकेले दिल्ली-एनसीआर में मानसून की पहली बारिश में अलग-अलग दुर्घटनाओं में छह लोग मारे गए। यह बरसात की शुरुआत का हाल है। आने वाले दिनों में जलभराव के साथ कहीं-कहीं बाढ़ की भी स्थिति देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भारी बरसात, भूस्खलन या फिर बादल फटने की घटनाओं से भी जान-माल को नुकसान हो सकता है।

केरल के जिस वायनाड में कुछ साल पहले भारी बरसात में कई लोग मारे गए थे,वहां बीते दिनों एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास भूस्खलन से तबाही मची। इसमें तीन लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस तरह की घटनाएं हमारे नीति-नियंताओं के लिए चिंता का कारण बननी चाहिए, क्योंकि वर्षा जनित समस्याओं के चलते लोगों की जान जाने के साथ शहरी ढांचे को अच्छा-खासा नुकसान भी होता है।

आखिर क्या कारण है कि जो मानसून देश की आर्थिकी के लिए अत्यधिक जरूरी है, वही ग्रामीण से लेकर शहरी इलाकों में तमाम समस्याओं को भी जन्म देता है? छोटे शहरों की बात तो दूर रही,देश के प्रमुख महानगर तक बारिश में गंभीर समस्याओं से घिर जाते हैं और उनमें जनजीवन बाधित हो जाता है। पिछले दिनों मुंबई में तीन दिन की भारी बरसात से आफत सी आ गई।
मुंबईवासियों को उन्हीं समस्याओं से फिर दो-चार होना पड़ा,जिनका सामना वे वर्षों से करते चले आ रहे हैं। इन समस्याओं से आजिज कुछ लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने मामले की सुनवाई करते हुए यह कहा कि जब लोग फुटपाथ, नदी-नालों,सड़कों पर अतिक्रमण कर लेंगे तो यह नौबत तो आएगी ही। उसके अनुसार मुंबई के हालात सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के दुरुपयोग के चलते खराब हुए।
अपने देश के बड़े शहर इसलिए और अधिक समस्याओं से घिर गए हैं, क्योंकि उनके बीच स्थित गांव और पुरानी बस्तियां अनियोजित विकास का पर्याय बन गई हैं। उनमें जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं होती और सीवेज सिस्टम भी दोयम दर्जे का होता है।

कभी इन गांवों की आबादी सीमित थी,लेकिन शहरीकरण के क्रम में उनकी आबादी हजारों और लाखों में हो गई है। आज दिल्ली-एनसीआर के कुछ गांवों में लाखों लोग रह रहे हैं। आम तौर पर ग्रामीण इलाकों से जो पलायन होता है, वह इन्हीं शहरी गांवों में आकर बसता है। नगर निकायों ने इन गांवों के आधारभूत ढांचे को ठीक करने के लिए जो कुछ किया है, वह ऊंट के मुंह में जीरे के सामान ही है।

नगर निकाय और राज्य सरकारें इन शहरीकृत गांवों में अनियोजित विकास को रोक नहीं पा रही हैं। इसका एक कारण यह है कि सभासदों यानी पार्षदों के एजेंडे में सुनियोजित विकास है ही नहीं। एक विडंबना यह भी है कि लोग शहरीकरण की चुनौतियों के समाधान के इरादे से सभासदों का चुनाव मुश्किल से ही करते हैं। यही स्थिति विधायकों और सांसदों के मामले में भी है। इसके चलते शहरों की रोजमर्रा की तकलीफें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अपने देश में अभी भी वोट जाति-पंथ या अन्य आधार पर दिए जाते हैं, न कि प्रत्याशी की योग्यता को देखकर।

रेलवे स्टेशनों के बुक स्टॉलों पर पसरा सन्नाटा
क्या इंटरनेट युग ने छीन ली पढ़ने की संस्कृति?

सत्यवान सौरभ
भिवानी,हरियाणा

भारतीय रेलवे स्टेशन केवल यात्रियों के आवागमन के केंद्र नहीं रहे हैं, बल्कि वे लंबे समय तक देश की सांस्कृतिक और बौद्धिक चेतना के भी प्रतीक रहे हैं। किसी भी बड़े या छोटे रेलवे स्टेशन पर प्रवेश करते ही व्हीलर जैसे बुक स्टॉल यात्रियों का ध्यान आकर्षित करते थे। यात्रा शुरू होने से पहले अखबार खरीदना, कोई पत्रिका चुनना या रास्ते के लिए उपन्यास लेना एक सामान्य आदत थी। रेल यात्रा और पुस्तकें मानो एक-दूसरे की पूरक थीं। लेकिन आज वही बुक स्टॉल सन्नाटे में डूबे दिखाई देते हैं। जिन स्थानों पर कभी पुस्तकों और पत्रिकाओं के खरीदारों की भीड़ लगी रहती थी,वहाँ अब गिने-चुने ग्राहक ही दिखाई देते हैं। अनेक स्टॉलों पर पुस्तकों की जगह पानी की बोतलें,बिस्कुट, चिप्स,कोल्ड ड्रिंक और अन्य खाद्य पदार्थों ने ले ली है। यह दृश्य केवल बाजार के बदलते स्वरूप का नहीं, बल्कि समाज की बदलती पठन संस्कृति का भी संकेत है।

पिछले दो दशकों में तकनीक ने मनुष्य के जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने सूचना तक पहुँच को आसान, तेज और सुलभ बना दिया है। आज दुनिया की लगभग हर जानकारी कुछ सेकंड में मोबाइल स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाती है। समाचार,पुस्तकें,शोध-पत्र,पत्रिकाएँ, वीडियो, पॉडकास्ट और ऑडियोबुक–सब कुछ एक ही उपकरण में समाहित हो गया है। यह तकनीकी क्रांति निस्संदेह मानव सभ्यता की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा प्रश्न भी जुड़ा है कि क्या इस डिजिटल सुविधा ने मुद्रित पुस्तकों और पत्रिकाओं की आवश्यकता को कम कर दिया है? रेलवे स्टेशनों के सूने पड़े बुक स्टॉल इस प्रश्न को और अधिक प्रासंगिक बना देते हैं।

एक समय था जब धर्मयुग,साप्ताहिक हिन्दुस्तान,कादम्बिनी,सारिका,नवनीत, रविवार,हंस,सरिता,मुक्ता,गृहशोभा, वनिता,मेरी सहेली,प्रतियोगिता दर्पण, चंदामामा,मधु मुस्कान,मायापुरी,मनोहर कहानियाँ,रीडर्स डाइजेस्ट,इंडिया टुडे और आउटलुक जैसी पत्रिकाओं की नई प्रतियों का पाठकों को बेसब्री से इंतजार रहता था। रेलवे स्टेशनों के बुक स्टॉल इन पत्रिकाओं के सबसे बड़े बिक्री केंद्र होते थे। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लाखों यात्री अपनी रुचि के अनुसार पत्रिकाएँ खरीदते थे। बच्चों के लिए कॉमिक्स, युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की सामग्री,महिलाओं के लिए गृह और परिवार से जुड़ी पत्रिकाएँ तथा साहित्य प्रेमियों के लिए उपन्यास और कहानी संग्रह आसानी से उपलब्ध रहते थे। यह केवल व्यापार नहीं था, बल्कि पढ़ने की एक जीवंत संस्कृति थी।
आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। अनेक प्रतिष्ठित पत्रिकाएँ बंद हो चुकी हैं। कई पत्रिकाओं का प्रकाशन सीमित हो गया है। जिनका प्रकाशन जारी भी है, उनकी प्रतियाँ पहले की तुलना में बहुत कम छपती हैं। पुस्तक विक्रेताओं का कहना है कि अब यात्रियों की पहली पसंद पुस्तक नहीं,बल्कि मोबाइल फोन है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा कर रहे अधिकांश लोग किताबों की अलमारी की ओर देखने के बजाय अपने मोबाइल की स्क्रीन में व्यस्त दिखाई देते हैं।

इस परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण इंटरनेट को माना जाता है। इंटरनेट ने ज्ञान और सूचना को लोकतांत्रिक बना दिया है। पहले किसी विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय जाना पड़ता था या पुस्तक खरीदनी पड़ती थी। आज वही जानकारी मुफ्त में ऑनलाइन उपलब्ध है। हजारों पुस्तकें पीडीएफ रूप में उपलब्ध हैं। किंडल और अन्य ई-बुक प्लेटफॉर्म ने पुस्तक पढ़ने के तरीके को बदल दिया है। ऑडियोबुक ने उन लोगों के लिए भी पढ़ने का विकल्प उपलब्ध कराया है जिनके पास समय कम है। इस दृष्टि से देखा जाए तो पढ़ने की आदत समाप्त नहीं हुई,बल्कि उसका माध्यम बदल गया है।

लेकिन यह आधा सच है। वास्तविक चिंता पढ़ने के माध्यम से अधिक पढ़ने की प्रवृत्ति को लेकर है। डिजिटल माध्यम पर उपलब्ध अधिकांश सामग्री त्वरित उपभोग के लिए तैयार की जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपयोग कर्ता का ध्यान अधिक समय तक किसी एक विषय पर टिकने नहीं देते। रील्स, शॉर्ट वीडियो और छोटे-छोटे पोस्ट लोगों को लगातार एक सामग्री से दूसरी सामग्री की ओर ले जाते रहते हैं। परिणामस्वरूप गहन अध्ययन,चिंतन और विश्लेषण की प्रवृत्ति कमजोर पड़ती जा रही है।
मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि लगातार बदलती डिजिटल सामग्री मनुष्य की एकाग्रता को प्रभावित करती है। पहले

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

लोग एक उपन्यास या पुस्तक को कई दिनों तक पढ़ते थे। अब कुछ मिनटों से अधिक समय तक एक ही विषय पर ध्यान केंद्रित करना कठिन होता जा रहा है। सूचना की मात्रा बढ़ी है, लेकिन ज्ञान की गहराई कम होती दिखाई देती है। यही कारण है कि पढ़ने और देखने के बीच का अंतर समझना आवश्यक है। वीडियो देखना और पुस्तक पढ़ना दो अलग-अलग मानसिक प्रक्रियाएँ हैं। पुस्तक पाठक को कल्पना,विश्लेषण और आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती है, जबकि वीडियो अधिकांश दृश्य सामग्री सीधे प्रस्तुत कर देता है।

रेलवे स्टेशनों के बुक स्टॉलों की बदली हुई तस्वीर केवल तकनीक की कहानी नहीं कहती,बल्कि बदलती जीवनशैली का भी संकेत देती है। आज लोगों के पास समय कम है और व्यस्तता अधिक है। लंबी रेल यात्राएँ भी अब मोबाइल मनोरंजन का माध्यम बन चुकी हैं। पहले चार घंटे की यात्रा में एक पुस्तक पढ़ी जाती थी, अब वही समय सोशल मीडिया, वेब सीरीज, गेम और वीडियो देखने में बीत जाता है।
शिक्षा व्यवस्था भी इस परिवर्तन से प्रभावित हुई है। विद्यार्थियों का अध्ययन अब परीक्षा-केंद्रित होता जा रहा है। पाठ्यक्रम से बाहर पढ़ने की आदत लगातार कम हो रही है। विद्यालयों और महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में पहले जैसी चहल-पहल दिखाई नहीं देती। डिजिटल नोट्स और ऑनलाइन कोचिंग ने मुद्रित अध्ययन सामग्री की आवश्यकता को काफी हद तक कम कर दिया है। हालांकि यह परिवर्तन सुविधाजनक है,लेकिन इसके कारण साहित्यिक और सामान्य पठन की परंपरा कमजोर हुई है।

परिवारों में भी पढ़ने का वातावरण पहले जैसा नहीं रहा। कभी बच्चों को जन्मदिन पर कहानी की पुस्तकें उपहार में दी जाती थीं। घरों में छोटी-छोटी पुस्तक अलमारियाँ होती थीं। समाचार पत्र पूरे परिवार द्वारा पढ़े जाते थे। आज बच्चों के हाथों में कम उम्र से ही स्मार्टफोन और टैबलेट आ गए हैं। मनोरंजन के डिजिटल विकल्प इतने अधिक हैं कि पुस्तकें उनके सामने आकर्षण खोती जा रही हैं।
यह भी सत्य है कि प्रकाशन उद्योग स्वयं समय के अनुरूप बदलाव करने में पूरी तरह सफल नहीं रहा। युवा पाठकों की बदलती रुचियों के अनुरूप सामग्री, आकर्षक प्रस्तुति और डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ संतुलित रणनीति विकसित करने में देर हुई। परिणामस्वरूप सोशल मीडिया ने पाठकों का बड़ा हिस्सा अपनी ओर आकर्षित कर लिया।

हालांकि पूरी तस्वीर निराशाजनक भी नहीं है। भारत में विश्व पुस्तक मेला, जयपुर साहित्य महोत्सव,क्षेत्रीय पुस्तक मेले और साहित्यिक आयोजनों में बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी यह बताती है कि अच्छी पुस्तकों के प्रति रुचि अभी भी समाप्त नहीं हुई है। ऑनलाइन पुस्तक बिक्री भी लगातार बढ़ रही है। इसका अर्थ है कि पाठक मौजूद हैं, लेकिन उनकी खरीदने और पढ़ने की आदत का स्वरूप बदल गया है।
आज आवश्यकता पुस्तक और डिजिटल माध्यम के बीच संघर्ष खड़ा करने की नहीं है। दोनों का संतुलित उपयोग ही समय की मांग है। ई-बुक और मुद्रित पुस्तकें दोनों साथ-साथ चल सकती हैं। रेलवे स्टेशनों पर आधुनिक डिजिटल बुक कियोस्क,स्थानीय भाषाओं की पुस्तकों का विशेष प्रदर्शन, बच्चों के लिए आकर्षक पुस्तक कोने तथा बुक कैफे जैसी अवधारणाएँ विकसित की जा सकती हैं। यदि यात्रियों को यात्रा के दौरान पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए तो बुक स्टॉलों की प्रासंगिकता फिर से बढ़ सकती है।

रेल मंत्रालय, प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं को मिलकर नई रणनीति बनानी होगी। स्टेशन पर केवल पुस्तक बेचने की बजाय पढ़ने का अनुभव उपलब्ध कराना होगा। स्थानीय साहित्य, क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें, यात्रा साहित्य,बच्चों की किताबें और समकालीन विषयों पर लोकप्रिय पुस्तकें प्रमुखता से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। डिजिटल भुगतान,ऑनलाइन ऑर्डर और स्टेशन से पुस्तक प्राप्त करने जैसी सुविधाएँ भी इस क्षेत्र में नई संभावनाएँ खोल सकती हैं।

विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी पठन संस्कृति को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। केवल परीक्षा की तैयारी ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं हो सकती। यदि विद्यार्थी साहित्य,इतिहास,विज्ञान, जीवनी और समाज से जुड़ी पुस्तकें नियमित पढ़ेंगे तो उनकी भाषा,विचार और व्यक्तित्व का समग्र विकास होगा। परिवारों को भी सप्ताह में कुछ समय स्क्रीन-फ्री रीडिंग के लिए निर्धारित करना चाहिए। यह छोटी-सी पहल बच्चों में आजीवन पढ़ने की आदत विकसित कर सकती है।
सरकार भी राष्ट्रीय स्तर पर रीडिंग कल्चर मिशन जैसी पहल शुरू कर सकती है। सार्वजनिक पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण,रेलवे स्टेशनों पर पुस्तकालय कोना, मोबाइल लाइब्रेरी और स्थानीय भाषा के साहित्य को बढ़ावा देने जैसी योजनाएँ पढ़ने की संस्कृति को नई ऊर्जा दे सकती हैं।

अंततः यह कहना उचित नहीं होगा कि इंटरनेट ने पुस्तकों का अंत कर दिया है। सच यह है कि इंटरनेट ने पढ़ने का तरीका बदल दिया है, लेकिन उसी के साथ उसने लोगों का ध्यान भी अनेक दिशाओं में बाँट दिया है। चुनौती तकनीक नहीं, बल्कि उसका असंतुलित उपयोग है। यदि मोबाइल ज्ञान का माध्यम बने तो वह पुस्तक का सहयोगी है, लेकिन यदि वह केवल मनोरंजन और त्वरित उपभोग तक सीमित रह जाए तो वह पढ़ने की संस्कृति के लिए चुनौती बन जाता है।

रेलवे स्टेशनों के बुक स्टॉलों पर पसरा सन्नाटा केवल घटती बिक्री की कहानी नहीं है। यह समाज के बदलते बौद्धिक व्यवहार का दर्पण है। यदि आने वाली पीढ़ियों में पढ़ने की आदत कमजोर होती गई तो इसका प्रभाव केवल प्रकाशन उद्योग पर नहीं, बल्कि लोकतंत्र,सामाजिक चेतना,भाषा, साहित्य और विचार की गुणवत्ता पर भी पड़ेगा। इसलिए समय की आवश्यकता यह नहीं कि तकनीक का विरोध किया जाए, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाए कि डिजिटल युग में भी पुस्तकें हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनी रहें। जब तक पुस्तकें जीवित रहेंगी, तब तक विचार जीवित रहेंगे,और जब विचार जीवित रहेंगे, तभी एक जागरूक,संवेदनशील और प्रगतिशील समाज का निर्माण संभव होगा।

गिरगिट ! तुम बेवजह बदनाम हो...

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उरतृप्त

एक पेड़ की झुकी हुई डाल पर बैठा बाघा गिरगिट बड़ी देर से सड़क किनारे खड़े इंसानों की महफिल देख रहा था। उसे अपनी पुश्तैनी रगों पर, अपने खानदानी हुनर पर बड़ा नाज़ था। जब चाहा, धानी पत्तों के बीच पन्ना बन गया; जब चाहा, सूखी टहनियों पर बैठ कत्थई चोला ओढ़ लिया। पर आज इंसानों की यह चुनावी और सामाजिक बैठकी देखकर उसकी पूंछ शर्म से दोहरे घेरे में मुड़ गई। उसने एक गहरी सांस ली,अपनी बाईं आंख को नब्बे डिग्री उत्तर और दाईं आंख को एक सौ अस्सी डिग्री दक्षिण में घुमाया और सोचने लगा कि विधाता ने उसे रंग बदलने की जो कला बख्शी थी, इंसानों ने तो उसका पूरा का पूरा कॉरपोरेट साम्राज्य ही खड़ा कर दिया है। बाघा ने हवा में उड़ते एक झींगुर को लपकने के लिए जीभ निकाली, पर फिर उसे लगा कि आज भोजन करने से ज़्यादा ज़रूरी आत्मनिरीक्षण है। वह समझ गया कि गिरगिट तो बस एक बदनाम विधा है,असली उस्ताद तो दो पैरों पर चलने वाला यह जीव है। गिरगिट तो केवल त्वचा का रंग बदलता है, इंसान तो अंतरात्मा का भूगोल ही बदल देता है। गिरगिट जब रंग बदलता है, तो उसका मक़सद बहुत सीधा और पाकीज़ा होता है, या तो पेट की आग बुझाना या फिर किसी शिकारी की बाज़ नज़रों से अपनी खाल बचाना।

भगवान राम का ध्यान और पर्यावरण की रक्षा जरुरी

संजय गोस्वामी
पटना,बिहार

आज भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या में चढ़ावा को लेकर चोरी के मामले सामने आ रहा है लेकिन याद कीजियेगा वो समय जब 1987 में रामानंद सागर की रामायण को टीवी पर दिखाई जाती थी लोग, दुकानदार दुकान बन्द कर ब्लैक एंड वाइट टीवी पर समय से पहले ही काम छोड़ कर दुकानदार दुकान बन्द कर यह सीरियस देखने का जो उत्साह था वो हमने उसके बाद कभी नहीं देखा रामायण एक बहुत ही सफल भारतीय टीवी श्रृंखला थी,जिसका निर्माण, लेखन और निर्देशन रामानन्द सागर के द्वारा किया गया था। 78-कड़ियों (एपिसोड) के इस धारावाहिक का मूल प्रसारण दूरदर्शन पर 25 जनवरी 1987 से 31 जुलाई 1988 तक चली इसका श्रेय स्व रामानंद सागर को जाता है और रामचरितमानस का श्रेय गोस्वामी तुलसीदासजी जाता है जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की जिससे हर घर में भगवान श्री राम के प्रति अपार आस्था प्रकट हुई गोस्वामी तुलसीदास अपने जीवनकाल से लेकर आजतक भारतीय जनमानस पर एकछत्र राज करते आ रहे हैं। तुलसी मात्र कवि ही नहीं हैं अपितु उनका स्थान हिन्दू संस्कृति के रक्षक,त्राता और उद्धर्ता के रूप में महत्वपूर्ण है। नैतिक विषयों पर धर्मशास्त्र का क्या कहना है, हम भारतीयों में यह चिंता अधिक नहीं है। हम प्रत्येक विषय पर तुलसी की राय जानना चाहते हैं और उसे प्रायः उद्धृत भी करते हैं,भगवान राम ने पिता की आज्ञा का पालन कर 14 वर्ष जंगल में बिताये जो यह दर्शाता है कि भगवान राम को शांति और प्राकृतिक सौंदर्य यथा पेड़ पौधे नदी मिट्टी और शुद्ध हवा से बहुत लगाव था आज हिन्दू समाज के भीतर रहकर जो लोग जनता को यह सिखाते थे कि मंदिरों में जाना व्यर्थ है, व्रत रखने से पुण्य नहीं होता और साकार की उपासना आंधविश्वासी मनुष्य करता है, ऐसे तत्वों के वे प्रबल विरोधी थे। एक दिन कोई अलख निरंजन की पुकार लगानेवाला फकीर उनके दरवाजे पर पहुँचा और अलख अलख का नारा लगाने लगा। तुलसी ने क्रोधित होकर कहा...

तुलसी अलख को देख चुका है,
तू रामनाम का जप कर!
हम लख हमहिं हमार लख,
हम-हमार के बीच,
तुलसी अलखहिं का लखै,
राम नाम जपु नीच।।

तुलसी नाथ-पंथियों और गोरख-पंथियों के भी विरुद्ध थे क्योंकि उनका विचार था कि इससे परंपरा कमजोर होती है और जनता का हृदय शून्यता से भरता जाता है। एक जगह उन्होंने लिखा कि गोरख ने ऐसा अलख जगाया कि लोगों की भक्ति भाग गई।

गोरख जगायो जोग,भगति भगायो लोग

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास ने मुफ्त का चंदन जितना भी घिसा हो, एक बात तो सार्वभौम सत्य है कि वे सन्त थे। उनकी रचना रामचरितमानस जैसा जीवन-विवेक और नीति-बोधवाला ग्रंथ विश्वसाहित्य में अनुपम है। एक-एक चौपाई और दोहे जीवन की हर परिस्थिति में विवेकपूर्ण और व्यावहारिक निर्णय लेने की क्षमता की शिक्षा देता है।
कबीर और तुलसी में फर्क है। तुलसी में नम्रता बहुत थी, इससे पता चलता है कि वे भी दुष्टों द्वारा सताए गए थे। बालकांड के आरंभ में ही वे सर्वप्रथम खलों और असंतों की लंबी वंदना करते हैं। वाणी और विनायक के स्मरण के पश्चात् वे तुरंत लिखते हैं...

बन्दौं प्रथम खलजन सतभाये।
जे बिनु काज दाहिने-बाएँ ।।

दुष्टों की प्रकृति का अद्भुत वर्णन है इस अंश में। चरम बिन्दु यह है....

पर अकाज लगि तन परिहरहीं।
जिमि हिम उपल कृषी दल गरहीं।।

दुष्ट दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपने प्राण दे देते हैं,जैसे ओला खेती का नाश करने के लिए अपने को गला देता है।
एक किंवदन्ती है कि तुलसी के इस मृदुल स्वभाव को देखते हुए एक दुष्ट उनकी कुटिया के बाहर खड़ा हो कर उन्हें देर से गरिया रहा था।आखिर तुलसीदास लाठी लेकर उसे मारने दौड़े। उसने कहा...रुकिए,आप मुझे नहीं मार सकते,आपने तो लिखा है कि...

बूँद अघात सहहिं गिरि ऐसे।

खल के वचन संत सह जैसे।।आप कैसे संत हैं जो लठियाने पर तुले हैं ?
तुलसी ने उसको छरपिटाने के बाद कहा... मैंने ये भी तो लिखा है...

अतिशय रगड़ करै जो कोई।
अनल प्रगट चंदन तैं होई ।।

मूलद्दसमस्या ये है कि तुलसी को कोई पढ़ता नहीं है, वे अब उदाहरण हो गए हैं, संत सब कोई और हैं ! साधु-संत अब गिरि कंदराओं में नहीं संसद के गलियारों में पाए जाते हैं। और जो अपनी साधना और सत्यनिष्ठा से संतत्व की प्राप्ति किए हुए हैं, उन्हें गरियाते हैं। राइस मिल से निकले चावल को अक्षत मानकर लहालोट होनेवाला वर्ग शंकराचार्यों से बड़ा धर्मज्ञाता बन बैठा है। वर्तमान परिस्थिति यह है...

हरित भूमि तृण संकुल
सूझ परहिं नहिं पंथ।
जिमि पाखंड विवाद तें,
लुप्त होहिं सद् ग्रंथ।।

मन का मयूरा..भोले

कार्तिकेय कुमार त्रिपाठी राम
इन्दौर,मध्यप्रदेश

मन का मयूरा भंवरे जैसा,
जब-जब घूमा करता है,
तब-तब आस बंधा करती है,
भोले से मिल जाने की।
मन का मयूरा ....
वो कब आए मन के द्वारे,
पता नहीं चल पाता है,
भोले भक्ति की डोर से बंधकर,
भोले की और खिंच जाता है।
मन का मयूरा ...
जीवन है एक राग पुराना,
भोले के संग मिलकर गाना,
पशुपतिनाथ के दर्शन करके,
पशु योनी फिर कभी नहीं पाना।
मन का मयूरा .....
निराकार है शिव की शक्ति,
जैसी तुम अंतस में बांधों,
डगर-डगर भोले की भक्ति,
से अपना जीवन तुम साधो।
मन का मयूरा .....
आओ भोले-भोले कहकर,
हम अपना जीवन तर जाएं,
सांझ सवेरे हम भोले संग,
मन भर कर हम सब मुस्कानें।
मन का मयूरा .....

केन की धारा में बहता एक सवाल–क्या इंसान भी विकास का हिस्सा है?

एक बाँध,हजार सवाल: केन-बेतवा के किनारे खड़ा भारत
जंगल हमारा,नदी हमारी : विकास की चिता पर जलते आदिवासी

प्रो. रितेश कुमार जैन
बड़वानी,मध्यप्रदेश

विकास तभी सार्थक है,जब उसकी कीमत किसी की पहचान, आजीविका और अस्तित्व न बने। आज भारत इसी प्रश्न के सामने खड़ा है। एक ओर देश की पहली नदी जोड़ो योजना के रूप में केन-बेतवा परियोजना है,जिसे जल,सिंचाई और ऊर्जा का समाधान बताया जा रहा है। दूसरी ओर पन्ना और छतरपुर के जंगलों में आदिवासी महिलाएँ चिता पर लेटकर, शरीर पर मिट्टी मलकर केवल दो वाक्यों में अपना दर्द कह रही हैं–जंगल हमारा, नदी हमारी और न्याय दो या मार दो। यह केवल विरोध नहीं,लोकतंत्र पर टूटते भरोसे की तस्वीर है। अब सवाल बाँध बनने का नहीं,बल्कि यह है कि विकास की परिभाषा आखिर किसके लिए लिखी जा रही है।
केन बेतवा परियोजना का प्रमुख हिस्सा दौधन बाँध है,जो पन्ना टाइगर रिजर्व के भीतर प्रस्तावित है। इससे लगभग 9 हजार हेक्टेयर भूमि, जिसमें कोर क्षेत्र का करीब 41.41 वर्ग किलोमीटर और बफर क्षेत्र शामिल हैं,डूबेगी। करीब 23 लाख पेड़ प्रभावित होने और केन नदी का प्राकृतिक प्रवाह बदलकर जल बेतवा में भेजने की आशंका है। सरकार के अनुसार इससे 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई, 62 लाख लोगों को पेयजल और 103 मेगावाट बिजली मिलेगी। लेकिन गोंड और कोल आदिवासियों के लिए यह केवल विकास नहीं,बल्कि अस्तित्व का सवाल है। उनके लिए जंगल सिर्फ पेड़ नहीं,बल्कि

इतिहास,संस्कृति,आजीविका और पहचान का आधार है।
वादों और ज़मीनी हकीकत की दूरी ने चिता आंदोलन फिर सुलगा दिया। प्रशासन के आश्वासन के बावजूद कई गाँवों में मकान तोड़े गए, बिजली कनेक्शन काटे गए, स्कूल ढहाए गए और विरोध करने वालों पर मुकदमे दर्ज हुए। दिव्या अहिरवार, लक्ष्मी आदिवासी सहित कई महिलाएँ विरोध में डटी रहीं, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर अनशन पर बैठे। उनका दावा है कि 7,000 से अधिक परिवार (लगभग 35-50 हजार लोग) विस्थापन की कगार पर हैं। उनके अनुसार संकट केवल घरों का नहीं,बल्कि जल,जंगल, जमीन,आजीविका और सांस्कृतिक पहचान का है। सवाल है–यदि विकास की कीमत आदिवासी समाज चुकाए और लाभ दूसरों को मिले, तो क्या यह न्यायपूर्ण विकास कहलाएगा?
इस संघर्ष का दायरा केवल विस्थापन नहीं,पूरे पारिस्थितिकी तंत्र तक है। पन्ना टाइगर रिजर्व का बड़ा हिस्सा डूबने की आशंका है,जिससे बाघों की पुनर्स्थापना, घड़ियाल संरक्षण और गिद्धों के प्राकृतिक घोंसले संकट में पड़ सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार वृक्ष कटाई और पारिस्थितिकी परिवर्तन से क्षेत्रीय वर्षा में करीब 12 प्रतिशत कमी आ सकती है। केन नदी का प्राकृतिक प्रवाह बदलने से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ने की आशंका है। आईआईटी बॉम्बे के वैज्ञानिक भी इसके प्राकृतिक तंत्र पर प्रभाव की चेतावनी दे चुके हैं। इसलिए आदिवासियों का जंगल हमारा,नदी हमारी कहना विकास विरोध नहीं, बल्कि प्रकृति और भविष्य की चिंता है।

किसी भी विस्थापन की सबसे बड़ी कीमत आँकड़े नहीं,इंसानी जिंदगियाँ चुकाती हैं। केनङ्कबेतवा परियोजना भी इसी सच्चाई के सामने है। आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार 7 हजार से अधिक परिवार प्रभावित होंगे और 22 गाँव डूब क्षेत्र में समा जाएँगे। पुनर्वास को लेकर असंतोष है। किसी को साढ़े बारह लाख, तो किसी को केवल साढ़े सात लाख रुपये मुआवजा मिल रहा है। वयस्क सदस्यों को अलग परिवार का दर्जा देने की माँग अधूरी है। आदिवासी समाज नकद नहीं,भूमि के बदले भूमि चाहता है, क्योंकि जंगल और खेत उसके जीवन का आधार हैं। आंदोलनकारियों का आरोप है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अधिकारों की अनदेखी हो रही है। पर्याप्त सूचना बिना मकान तोड़े जाने से प्रशासन और समाज के बीच भरोसे की खाई गहरी हुई है।

तस्वीर का दूसरा पहलू भी अहम है। सरकार का तर्क है कि भविष्य की जल जरूरतों के लिए बड़े समाधान जरूरी हैं। सिंचाई, पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल है कि किसी परियोजना का मूल्य केवल लाभ से तय होगा या उसकी सामाजिक और पर्यावरणीय कीमत से भी।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
सम्पादक

'सांड राज' की चेतावनी हुई सच,महिला की मौत के बाद जागा सिस्टम

चार महीने पहले उठा था सवाल... 'कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा',अब भातूपारा की महिला की मौत ने खोल दी नगर निगम की व्यवस्था की पोल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,12 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

शहर में आवारा सांडों का आतंक आखिर एक महिला की जान ले गया। भातूपारा में सांड के हमले में गंभीर रूप से घायल हुई वीवी बाई की रायपुर के डीकेएस अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद नगर निगम ने आवारा सांडों को पकड़ने के निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब पिछले कई महीनों से लगातार चेतावनियां मिल रही थीं, शिकायतें हो रही थीं और लोग घायल हो रहे थे, तब जिम्मेदार विभाग ने स्थायी कार्रवाई क्यों नहीं की? दरअसल,यह पहली बार नहीं है जब शहर में आवारा सांडों का मुद्दा सुर्खियों में आया हो। 20 मार्च 2026 को केदारपुर भट्ठी रोड स्थित गणेश दादा गली में दो आक्रामक सांडों के आतंक को लेकर विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। उस समय स्थानीय लोगों ने बताया था कि सांड बिना किसी उकसावे के राहगीरों पर हमला कर रहे हैं। बच्चे,महिलाएं और बुजुर्ग घर से निकलने में डर रहे थे। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे,जिनमें एक व्यक्ति का हाथ फ्रैक्चर तक हो गया था। उस समय भी लोगों ने चेतावनी दी थी कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

चेतावनी को नजरअंदाज किया,अब गई एक जान : मार्च में प्रकाशित रिपोर्ट के बाद कुछ समय के लिए निगम की टीम ने एक सांड को पकड़कर शहर से बाहर छोड़ा था,लेकिन वह कुछ ही समय बाद वापस लौट आया। इसके बाद फिर वही हालात बन गए। इसका मतलब साफ था कि समस्या का समाधान नहीं, केवल खानापूर्ति की गई। इसी बीच शहर के अलग-अलग हिस्सों में सांडों के हमले जारी रहे। कुछ दिन पहले गांधी चौक पर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस के जवान पर सांड ने हमला कर दिया। जवान गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। भाठूपारा में भी एक अन्य व्यक्ति पहले सांड के हमले में घायल हो चुका था। इन घटनाओं के बावजूद व्यापक अभियान नहीं चलाया गया।

हर हादसे के बाद वही आश्वासन : शहरवासियों का आरोप है कि नगर निगम की कार्रवाई केवल किसी बड़े हादसे के बाद ही दिखाई देती है। कुछ दिन अभियान चलता है, कुछ मवेशी पकड़े जाते हैं,फिर अभियान बंद होते ही सांड दोबारा सड़कों पर लौट आते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि अब तक अपनाई गई व्यवस्था पूरी तरह असफल साबित हुई है।

पानी भर रही महिला पर हमला, इलाज के दौरान मौत

शुक्रवार सुबह भातूपारा निवासी वीवी बाई घर के पास सार्वजनिक नल से पानी भर रही थीं। इसी दौरान एक आवारा सांड ने उन पर अचानक हमला कर दिया। सांड ने उन्हें सींग से उठाकर कई फीट दूर पटक दिया। गंभीर हालत में पहले मेडिकल कॉलेज अस्पताल और बाद में रायपुर के डीकेएस अस्पताल रेफर किया गया,जहां रविवार को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद पूरे शहर में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि यदि मार्च में ही प्रशासन ने चेतावनी को गंभीरता से लिया होता तो शायद आज यह नौबत नहीं आती।

शहर के हर प्रमुख मार्ग पर सांडों का कब्जा

गांधी चौक,देवीगंज रोड,गुदरी बाजार,आकाशवाणी चौक,संगम चौक,बस स्टैंड, भातूपारा और कई अन्य व्यस्त क्षेत्रों में सुबह से रात तक आवारा सांड और मवेशी घूमते दिखाई देते हैं। कई बार सांड आपस में लड़ते हुए सड़क पर दौड़ पड़ते हैं,जिससे दुर्घटना का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और दोपहिया चालक सबसे अधिक जोखिम में रहते हैं।

पशु मालिकों पर क्यों नहीं होती कार्रवाई? स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सड़कों पर घूम रहे अधिकांश मवेशियों के मालिक हैं,लेकिन कार्रवाई केवल पशुओं को पकड़ने तक सीमित रहती है। न तो पशु मालिकों पर प्रभावी जुर्माना लगाया जाता है और न ही उनकी जवाबदेही तय की जाती है। यही वजह है कि समस्या लगातार बढ़ती जा रही है।

महापौर ने दिए निर्देश, लेकिन जनता को स्थायी समाधान चाहिए: महापौर मंजूषा भगत ने महिला की मौत पर दुःख व्यक्त करते हुए नगर निगम आयुक्त को तत्काल आवारा सांडों को पकड़ने के निर्देश दिए हैं। निगम का कहना है कि सांडों को सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा तथा उनके चारा-पानी की व्यवस्था भी की जाएगी। हालांकि शहरवासियों का कहना है कि केवल निर्देशों और अभियानों से अब भरोसा नहीं बनेगा। उन्हें ऐसा स्थायी समाधान चाहिए जिससे भविष्य में किसी और परिवार को इस तरह की त्रासदी का सामना न करना पड़े।

अब जवाब चाहिए, सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन नहीं...

भातूपारा की महिला की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं—

- जब मार्च से लगातार शिकायतें और हमले हो रहे थे तो व्यापक अभियान क्यों नहीं चलाया गया?
- क्या नगर निगम के पास आवारा मवेशियों के प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था नहीं है?
- क्या पशु मालिकों पर कार्रवाई के नियम केवल कागजों तक सीमित हैं?
- क्या हर बार किसी की जान जाने के बाद ही प्रशासन सक्रिय होगा?

अब यह केवल आवारा मवेशियों का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि शहर में प्रशासनिक जवाबदेही और नागरिकों की सुरक्षा का प्रश्न बन चुका है। यदि इस घटना के बाद भी ठोस और स्थायी कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति से इनकार नहीं किया जा सकता।

'सुपरमैन' की एक और कार्रवाई.... लेकिन नशे का नेटवर्क अब भी कायम

ब्रह्मपारा से आशा पांडेय गिरफ्तार,28 नशीले इंजेक्शन जब्त,लगातार दबिश के बावजूद सरगुजा में क्यों सामने आ रहे नए-नए सौदागर?

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,12 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

संभागीय आबकारी उड़नदस्ता प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुपरमैन कहे जाने वाले रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में चल रहे 'ऑपरेशन क्लीन' के तहत रविवार को ब्रह्मपारा क्षेत्र में एक और कार्रवाई की गई। आबकारी टीम ने आशा पांडेय नामक महिला को 28 नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेज दिया। विभाग के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि ब्रह्मपारा निवासी आशा पांडेय अपने घर से नशीले इंजेक्शन बेच रही है। सूचना के आधार पर टीम ने दबिश दी। कार्रवाई के दौरान महिला कथित रूप से एक थैला फेंकने का प्रयास कर रही थी, जिसे मौके पर मौजूद महिला सैनिक ने पकड़ लिया। तलाशी में 19 नग REXOGESIC और 9 नग AVIL इंजेक्शन बरामद किए गए। आबकारी विभाग का कहना है कि आशा पांडेय पहले ब्राउन शुगर से जुड़े मामले में जेल जा चुकी है और अब नशीले इंजेक्शन बेचने की सूचना पर कार्रवाई की गई है।

लगातार बढ़ती कार्रवाई,लेकिन खत्म नहीं हो रहा कारोबार

यह पिछले कुछ सप्ताह में आबकारी उड़नदस्ता की एक और बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले...

- वाहिद अंसारी की गिरफ्तारी के बाद मोशीम अंसारी तक टीम पहुंची।
- लुंड्रा क्षेत्र से कथित सप्लायर पकड़े गए।
- सूरजपुर में प्रदीप राजवाड़े गिरफ्तार हुआ।
- श्याम लॉज से साहिल तिर्की पकड़ा गया, जिसके बाद नितीश गुप्ता को गिरफ्तार किया गया।
- सीतापुर से 3,528 नशीले कैप्सूल जब्त कर दो आरोपियों को जेल भेजा गया।
- महुआ शराब और अवैध शराब बिक्री के मामलों में भी लगातार कार्रवाई हुई।

अब इस कड़ी में ब्रह्मपारा से आशा पांडेय की गिरफ्तारी जुड़ गई है।

हर कार्रवाई के बाद नया नाम क्यों?

लगातार हो रही गिरफ्तारियां एक ओर विभाग की सक्रियता को दर्शाती हैं,लेकिन दूसरी ओर एक गंभीर सवाल भी खड़ा करती हैं। यदि अभियान लगातार सफल है तो हर कुछ दिनों में एक नया विक्रेता,नया सप्लायर या नई खेप कैसे सामने आ रही है? यह स्थिति संकेत देती है कि स्थानीय स्तर पर कार्रवाई के बावजूद नशे की आपूर्ति का स्रोत पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।

जांच की असली चुनौती सप्लाई नेटवर्क

अब तक अधिकांश मामलों में बरामदगी और स्थानीय स्तर पर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन यह सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन आरोपियों तक नशीले इंजेक्शन पहुंचाने वाली बड़ी सप्लाई चेन कहां से संचालित हो रही है।

- क्या जब्त इंजेक्शनों की सप्लाई का स्रोत चिन्हित किया गया?
- क्या बैच नंबर के आधार पर वितरण श्रृंखला की जांच की गई?
- क्या औषधि प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वित जांच आगे बढ़ी?

इन सवालों के जवाब सामने आना अभी बाकी हैं।

केवल गिरफ्तारियां नहीं,नेटवर्क पर प्रहार की अपेक्षा

- नशे के खिलाफ अभियान की सफलता केवल इस आधार पर नहीं आंकी जाती कि कितने आरोपी गिरफ्तार हुए या कितनी खेप जब्त हुई।
- वास्तविक सफलता तब मानी जाती है जब अवैध सप्लाई चेन,वित्तीय नेटवर्क और संगठित तंत्र तक कार्रवाई पहुंचे, जिससे बार-बार नए नाम सामने आने की स्थिति समाप्त हो।
- फिलहाल ब्रह्मपारा की यह कार्रवाई 'ऑपरेशन क्लीन' की एक और कड़ी है,लेकिन सरगुजा में नशीले इंजेक्शनों के लगातार सामने आते मामलों ने यह संकेत भी दिया है कि नशे के कारोबार के खिलाफ लड़ाई अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।

खनिजों से अरबों की कमाई,लेकिन गांव अब भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित : मनोज दुबे

डीएमएफ निधि का सामाजिक अंकेक्षण कराने और वर्षवार खर्च सार्वजनिक करने की मांग,सरकार से जवाबदेही तय करने की अपील

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,12 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

खनिज संपदा से समृद्ध सरगुजा संभाग में विकास कार्यों को लेकर एक बार फिर जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि के उपयोग पर सवाल उठे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज दुबे ने आरोप लगाया कि कोयला, बॉक्साइट सहित अन्य खनिजों से प्रदेश सरकार को वर्षों से करोड़ों रुपये का राजस्व मिल रहा है, लेकिन जिन क्षेत्रों से यह संपदा निकल रही है, वहीं के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिलों में बड़े पैमाने पर कोयले का खनन तथा मैनपाट क्षेत्र में बॉक्साइट का उत्खनन होता है। इन क्षेत्रों के विकास के लिए डीएमएफ के माध्यम से हर वर्ष बड़ी राशि उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन इसका अपेक्षित लाभ खनन प्रभावित गांवों तक नहीं पहुंच रहा है। मनोज दुबे ने कहा कि कई गांवों में आज भी सड़क,स्वास्थ्य सुविधा, स्वच्छ पेयजल,सिंचाई, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। दूसरी ओर खनन गतिविधियों के कारण धूल प्रदूषण, खराब सड़कों और पर्यावरणीय समस्याओं का खामियाजा स्थानीय लोगों को उठाना पड़ रहा है।

वर्षवार हिसाब सार्वजनिक करने की मांग

आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार से मांग की है कि सरगुजा संभाग के सभी जिलों में डीएमएफ निधि का वर्षवार और कार्यवार पूरा लेखा-जोखा सार्वजनिक किया जाए। इसमें यह स्पष्ट किया जाए कि कितनी राशि प्राप्त हुई, किन योजनाओं पर खर्च की गई, कितने कार्य पूर्ण हुए, कितने अधूरे हैं तथा उन कार्यों से स्थानीय लोगों को कितना लाभ मिला।

ग्राम सभा की निगरानी में हो सोशल ऑडिट

पार्टी ने मांग की कि प्रत्येक खनन प्रभावित ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की उपस्थिति में सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) कराया जाए। साथ ही सभी स्वीकृत परियोजनाओं,उनकी लागत, प्रगति और खर्च की जानकारी सार्वजनिक पोर्टल एवं ग्राम पंचायतों के सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित की जाए,ताकि आम नागरिक भी निगरानी कर सकें।

जनता के धन का लाभ जनता को मिले

मनोज दुबे ने कहा कि यदि सरगुजा की खनिज संपदा का लाभ सबसे पहले स्थानीय लोगों को नहीं मिलता तो विकास की अवधारणा अधूरी रह जाती है। उन्होंने सरकार से मांग की कि डीएमएफ निधि का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर अस्पताल, स्कूल, पेयजल,सिंचाई,सड़क, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय युवाओं के रोजगार सृजन पर किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि डीएमएफ निधि के उपयोग में कहीं अनियमितता, लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की शिकायतें हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उनका कहना था कि जनता के विकास के लिए बनी निधि का उपयोग पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ होना चाहिए।

डायल-112 के प्रभावी संचालन हेतु 107 पुलिसकर्मियों को मिला विशेष प्रशिक्षण

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,12 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

डायल-112 (फेज-2 नेक्स्ट जेनरेशन) सेवा को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से रक्षित केंद्र अंबिकापुर में सरगुजा एवं बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देशन में आयोजित इस प्रशिक्षण में दोनों जिलों के कुल 107 अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए। सी-डैक (C-DAC) के मास्टर ट्रेनर एवं प्रोजेक्ट मैनेजर गौरव वर्मा तथा विजन प्लस के गोविंदा ने डायल-112 आपातकालीन वाहनों में स्थापित पीएफटी,एमडीटी,मोबाइल,पीटीजेड कैमरा, डैश कैमरा सहित अन्य तकनीकी उपकरणों के संचालन एवं रखरखाव की व्यवहारिक जानकारी दी। प्रशिक्षण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं डायल-112 के नोडल अधिकारी अमोलक सिंह ढिल्लों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में बताया गया कि 18 मई 2026 से राज्यभर में डायल-112 फेज-2 सेवा संचालित है, जिसके माध्यम से नागरिक एक ही नंबर 112 पर पुलिस, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

अधिकारियों ने घटनास्थल तक त्वरित पहुंच, जीपीएस आधारित लोकेशन ट्रैकिंग तथा आम नागरिकों को बेहतर आपातकालीन सेवा उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। साथ ही पीटीजेड कैमरा एवं अन्य उपकरणों की नियमित जांच और सही संचालन के निर्देश भी दिए गए। प्रशिक्षण में ईआरवी स्टाफ,थाना-चौकी,रक्षित केंद्र,यातायात शाखा एवं हाईवे पेट्रोलिंग के अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

किरायेदारों के सत्यापन की मांग के बाद पुलिस का दूसरा बड़ा अभियान

पार्षद आलोक दुबे के ज्ञापन के बाद लगातार कार्रवाई अब 350 मकानों में 750 लोगों का भौतिक सत्यापन

पहले 125 स्थानों पर 450 लोगों की हुई थी जांच,अब शहर और ग्रामीण क्षेत्रों तक अभियान का विस्तार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,12 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

बाहरी राज्यों से आए किरायेदारों के व्यापक सत्यापन की मांग उठने के बाद सरगुजा पुलिस लगातार अभियान चला रही है। नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद आलोक दुबे द्वारा सरगुजा रेंज के आईजी को ज्ञापन सौंपकर किरायेदारों के सत्यापन और मकान मालिकों की जवाबदेही तय करने की मांग किए जाने के बाद पुलिस ने दूसरी बार बड़े स्तर पर सघन जांच अभियान चलाया। इस बार जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 350 मकानों में रह रहे करीब 750 लोगों का भौतिक सत्यापन किया गया। इससे पहले भी पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 125 मकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में 450 लोगों के दस्तावेजों की जांच की थी।

पार्षद आलोक दुबे ने अपने ज्ञापन में कहा था कि अंबिकापुर के गांधीनगर, कोतवाली और मणिपुर थाना क्षेत्रों सहित कई मोहल्लों में बाहरी राज्यों से आए लोग बिना समुचित पुलिस सत्यापन के किराये के मकानों में रह रहे हैं। उन्होंने आशंका जताई थी कि यदि समय रहते उनकी पहचान और पृष्ठभूमि की जांच नहीं हुई तो भविष्य में कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने प्रत्येक किरायेदार का पुलिस सत्यापन अनिवार्य करने और ऐसा नहीं करने वाले मकान मालिकों की जवाबदेही तय करने की मांग की थी।

लगातार दूसरे चरण में चला अभियान : डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल के निर्देशन में सभी थाना और चौकी प्रभारियों को बाहरी व्यक्तियों, किरायेदारों और मुसाफिरों के सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं। इसी के तहत राजपत्रित अधिकारियों की निगरानी में जिलेभर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस टीमों ने गांधीनगर थाना क्षेत्र के सुभाषनगर,भगवानपुर और फूंदुरडिहारी, कोतवाली थाना क्षेत्र के नवागढ़ और सत्तीपारा,तथा मणिपुर थाना क्षेत्र के बंजारी,लक्ष्मीपुर और मठपारा सहित उन बस्तियों में विशेष जांच की,जहां बाहरी राज्यों से आए लोगों की संख्या अधिक है। अभियान के दौरान किरायेदारों और मुसाफिरों से पूछताछ की गई तथा उनके पहचान पत्रों का भौतिक सत्यापन किया गया।

मकान मालिकों को सख्त निर्देश

पुलिस ने मकान मालिकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना सत्यापन किसी भी व्यक्ति को किराये पर मकान न दें। किरायेदार का पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, स्थायी पता और अन्य आवश्यक जानकारी संबंधित थाना या चौकी में उपलब्ध कराना अनिवार्य बताया गया है। बिना सत्यापन क्षेत्र में रह रहे संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई और आवश्यकता पड़ने पर निर्वासन की कार्रवाई भी की जाएगी।

दो चरणों में 1,200 लोगों का सत्यापन

पुलिस के अनुसार अब तक चलाए गए दो प्रमुख अभियानों में कुल 475 मकानों और प्रतिष्ठानों की जांच की जा चुकी है। पहले अभियान में 125 स्थानों पर 450 लोगों, जबकि दूसरे अभियान में 350 मकानों में 750 लोगों का सत्यापन किया गया। पुलिस का कहना है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

C M Y K

नौगई तिहरे हत्याकांड में बड़ा अपडेट....बैकुंठपुर पहुंच सकती है CBI की टीम,नए सिरे से होगी पूरे मामले की जांच : सूत्र

पीड़ित परिवार की सीबीआई जांच की मांग को मिल सकती है मंजूरी,पुलिस की शुरुआती जांच भी आ सकती है जांच के दायरे में...

रवि सिंह

बैकुंठपुर/कोरिया,12 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिले के बहुचर्चित नौगई तिहरे हत्याकांड मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आने की संभावना है,विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, मामले की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की टीम जल्द ही बैकुंठपुर पहुंच सकती है,यदि ऐसा होता है तो इस जघन्य हत्याकांड की जांच नए सिरे से शुरू होगी और अब तक की पुलिस विवेचना सहित पूरे घटनाक्रम की गहन पड़ताल की जाएगी। गौरतलब है कि 16 और 17 जून की दरम्यानी रात सोनहत थाना क्षेत्र के ग्राम नौगई में हुए तिहरे हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था, आरोप है कि एक ही परिवार के कई लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से दूसरे परिवार पर उस समय हमला कर दिया,जब पीड़ित पक्ष तीन वाहनों से समझौते की नीयत से आरोपितों के घर पहुंचा था,पीड़ित पक्ष का आरोप है कि विवाद रेत कारोबार और कथित रंगदारी की मांग से जुड़ा था,उनका कहना है कि आरोपित बिना रॉयल्टी के रेत कारोबार करने की अनुमति चाहते थे और इसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया,हमले के दौरान लाठी-डंडों और अन्य घातक हथियारों से हमला करने के साथ-साथ पीड़ितों को जिंदा जलाने का प्रयास भी किया गया,इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हुए।

स्थानीय पुलिस की जांच पर शुरू से उठते रहे सवाल

घटना के बाद पीड़ित परिवार ने स्थानीय पुलिस की जांच पर भरोसा न जताते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। परिवार का आरोप था कि घटना की प्रारंभिक विवेचना और अधिकारियों के सार्वजनिक बयानों से उन्हें निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं रही,पीड़ित पक्ष लगातार यह दावा करता रहा कि आग पेट्रोल डालकर लगाई गई थी,जबकि प्रारंभिक स्तर पर आग लगने के कारणों को लेकर अलग-अलग बातें सामने आई थीं।

हर पहलू की हो सकती है दोबारा जांच

सूत्रों की मानें तो यदि सीबीआई जांच शुरू होती है,तो एजेंसी घटना से जुड़े सभी पहलुओं की स्वतंत्र जांच कर सकती है,इसमें घटनास्थल के साक्ष्य,फॉरेंसिक रिपोर्ट, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान,मोबाइल कॉल डिटेल,पोस्टमार्टम रिपोर्ट,आगजनी के कारण तथा पुलिस की शुरुआती कार्रवाई और विवेचना की भी समीक्षा की जा सकती है।

पीड़ित परिवार को पहले मिला था आश्वासन

जानकारी के अनुसार,पीड़ित परिवार को पूर्व में शासन स्तर से सीबीआई जांच की मांग पर सकारात्मक संकेत भी मिले थे,अब सूत्रों के हवाले से सीबीआई टीम के बैकुंठपुर पहुंचने की चर्चा तेज होने के बाद मामले में नई उम्मीद जगी है।

आधिकारिक पुष्टि का इंतजार

हालांकि, सीबीआई, राज्य शासन अथवा जिला प्रशासन की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है,इसलिए फिलहाल सीबीआई टीम के आगमन और जांच शुरू होने की जानकारी सूत्रों पर आधारित है,आधिकारिक पुष्टि होने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी,अब पूरे जिले की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या बहुचर्चित नौगई तिहरे हत्याकांड की जांच वास्तव में सीबीआई अपने हाथ में लेती है और क्या इससे घटना से जुड़े सभी विवादित पहलुओं पर अंतिम रूप से पर्दा उठ सकेगा।

सीतापुर के बगडोली में खसरे की दस्तक,छह बच्चों में संक्रमण की पुष्टि

15 संदिग्ध बच्चों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे,स्वास्थ्य विभाग ने गांव में शुरू किया विशेष सर्वे और टीकाकरण अभियान

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,12 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के सीतापुर विकासखंड के बगडोली गांव में खसरे (मीजल्स) के छह मामलों की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। संदिग्ध लक्षण मिलने पर 15 बच्चों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे,जिनमें छह बच्चों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके बाद गांव में विशेष स्वास्थ्य टीम तैनात कर उपचार, घर-घर सर्वे और टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गांव के कुछ बच्चों में तेज बुखार और शरीर पर लाल चकत्ते (दाने) उभरने की शिकायत मिलने पर सैंपल लेकर जांच के लिए

जबलपुर स्थित इम्यूनोलॉजी लैब भेजे गए थे। जांच रिपोर्ट में छह बच्चों में मीजल्स संक्रमण की पुष्टि होने के बाद विभाग ने प्रभावित क्षेत्र में रोकथाम के लिए विशेष अभियान प्रारंभ कर दिया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी.एस. मार्को तथा महामारी नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. शैलेंद्र गुप्ता के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग की टीम बगडोली पहुंची। टीम ने स्वास्थ्य शिविर लगाकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण शुरू किया है। संक्रमित बच्चों का उपचार किया जा रहा है, वहीं अन्य बच्चों को विटामिन-ए की खुराक देने के साथ उनका नियमित टीकाकरण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे गांव में घर-घर सर्वे शुरू किया है,ताकि बुखार,खांसी और शरीर पर दाने जैसे लक्षण वाले अन्य बच्चों की समय रहते पहचान कर उनका उपचार किया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि संक्रमण को आसपास के क्षेत्रों में फैलने से रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है और स्वास्थ्य दल लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अधिक खतरा : चिकित्सकों के अनुसार खसरा पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अधिक गंभीर हो सकता है। इसकी शुरुआत आमतौर पर तेज बुखार, खांसी, जुकाम और शरीर पर लाल चकत्तों से होती है।

समय पर उपचार और टीकाकरण नहीं होने पर रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ सकती है, जिससे निमोनिया सहित अन्य गंभीर जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है।

स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि यदि बच्चों में बुखार, खांसी,आंखों में लाली या लाल दाने जैसे लक्षण दिखाई दें तो तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं और बच्चों का टीकाकरण समय पर अवश्य पूरा कराएं।

प्रेम विवाह के सात साल बाद दिव्यांग महिला की संदिग्ध मौत,मायके पक्ष ने जताई हत्या की आशंका....

घर में फंदे पर मिला शव, पति पर प्रताड़ना का आरोप,पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार में पुलिस,सभी पहलुओं की जांच जारी

-संवाददाता-

लखनपुर,12 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

कुन्नी चौकी क्षेत्र के ग्राम कोटबर्रा में प्रेम विवाह के सात वर्ष बाद एक दिव्यांग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। शनिवार दोपहर महिला का शव घर के भीतर फंदे से लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही मायके पक्ष मौके पर पहुंचा और हत्या कर शव को फंदे पर लटकाने की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सकरिया निवासी 35 वर्षीय पावरो पैंकरा, जो पैर से दिव्यांग थीं, ने करीब सात वर्ष पहले कोटबर्रा निवासी अमरूद मझवार से प्रेम विवाह किया था। दंपती के तीन बच्चे हैं। मृतका के परिजनों का आरोप है कि पति शराब के नशे में अक्सर विवाद करता था और महिला के साथ मारपीट व प्रताड़ना करता था। बताया गया कि शनिवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे पति ने मृतका के मायके में फोन कर बताया कि पावरो ने फांसी लगा ली है। जब परिजन कोटबर्रा पहुंचे तो महिला का शव फंदे से नीचे उतारा जा चुका था। परिजनों के अनुसार पति और ससुर ने शव को फंदे से उतारा था। इसी बात को लेकर मायके पक्ष ने घटना पर संदेह व्यक्त करते हुए हत्या की आशंका जताई। घटना की सूचना पर रविवार सुबह एसडीओपी तुल सिंह पट्टावी एवं कुन्नी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए लखनपुर अस्पताल भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। कुन्नी चौकी में पदस्थ प्रधान आरक्षक बलभद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है,लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि होगी। उन्होंने कहा कि मायके पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को भी जांच में शामिल किया गया है और पुलिस सभी पहलुओं पर निष्पक्ष जांच कर रही है।

मोरभंज में मौत को दावत देता कार स्टंट,वायरल वीडियो ने खोली लापरवाही की पोल

पर्यटन स्थल पर खुले दरवाजों से लटककर दौड़ाई कारें,वीडियो की पुष्टि नहीं लेकिन सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी पर उठे सवाल

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,12 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार चल रहे जागरूकता अभियानों और पुलिस की सख्ती के बावजूद युवाओं में खतरनाक स्टंट का जुनून कम होता नहीं दिख रहा है। सूरजपुर जिले के अजबनगर से लगे पर्यटन स्थल मोरभंज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कई युवक कारों से बेहद जोखिम भरे स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वीडियो कब का है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है,लेकिन इसमें दिख रहे दृश्य यातायात नियमों की खुली अनदेखी और जानलेवा लापरवाही की ओर इशारा करते हैं। वायरल वीडियो में 4 से 5 कारों का काफिला मोरभंज डेम के पास स्टंट करता नजर आ रहा है। कुछ युवक कार के दरवाजे खोलकर बाहर लटकते हुए वाहन चला रहे हैं, जबकि कुछ कारों को आगे-पीछे तेज रफ्तार में दौड़ाकर करतब दिखा रहे हैं। उनके साथ मौजूद अन्य युवक इन स्टंटों का वीडियो बनाते और उत्साह बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। यह पूरा घटनाक्रम न केवल स्टंट करने वालों की जान जोखिम में डालता है,बल्कि वहां घूमने आए अन्य पर्यटकों के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है।

मोरभंज,अजबनगर से करीब चार किलोमीटर और अंबिकापुर से लगभग दस किलोमीटर दूर स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। पिल्खा पहाड़ की तलहटी और डेम का प्राकृतिक सौंदर्य बड़ी संख्या में पर्यटकों, परिवारों और युवाओं को आकर्षित करता है। छुट्टियों और सप्ताहांत पर यहां काफी भीड़ रहती है। ऐसे स्थान पर इस तरह की लापरवाही किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है।

पहले भी हो चुके हैं हादसे : स्थानीय लोगों के अनुसार मोरभंज डेम क्षेत्र में पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बावजूद कुछ युवाओं द्वारा इसे स्टंट का मैदान बना देना चिंता का विषय है। यदि स्टंट के दौरान वाहन अनियंत्रित हो जाए या कोई पर्यटक इसकी चपेट में आ जाए तो गंभीर जनहानि हो सकती है।

सिर्फ चालान नहीं, मानसिकता बदलने की जरूरत : यातायात विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में केवल चालान या जुर्माना पर्याप्त नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल होने और लोकप्रियता पाने की होड़ युवाओं को खतरनाक हरकतों की ओर धकेल रही है। ऐसे मामलों में वाहन जब्ती, ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन और अभिभावकों की जवाबदेही तय करने जैसी सख्त कार्रवाई भी आवश्यक है।

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले : अंबिकापुर शहर में भी स्कूल फेयरवेल और अन्य आयोजनों के दौरान

कारों से स्टंट करते छात्र-छात्राओं के वीडियो वायरल हो चुके हैं। उन मामलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभिभावकों पर जुर्माना लगाया था। इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं दोबारा सामने आना यह दर्शाता है कि सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता और कानून के पालन में अभी भी बड़ी कमी है।

निगरानी बढ़ाने की मांग : स्थानीय लोगों का कहना है कि मोरभंज जैसे पर्यटन स्थलों पर सप्ताहांत और छुट्टियों के दौरान नियमित पुलिस गश्त, सीसीटीवी निगरानी और विशेष अभियान चलाए जाने चाहिए। इससे स्टंटबाजी पर अंकुश लगेगा और पर्यटकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी।

सुदूर आदिवासी गांव बुले खासपारा में शाला प्रवेश उत्सव,सात नवप्रवेशी बच्चों का हुआ स्वागत

मड़वार समुदाय के बच्चों को तिलक लगाकर दी पाठ्य सामग्री, डीईओ ने कहा...शिक्षा ही बेहतर भविष्य की मजबूत नींव

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,12 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

सुदूर आदिवासी क्षेत्र के बुले खासपारा स्थित प्राथमिक विद्यालय में शाला प्रवेश उत्सव उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी दिनेश झा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने मझवार समुदाय के सात नवप्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक लगाकर स्वागत किया और उन्हें पाठ्यपुस्तकें, कॉपी, पेन एवं बेल्ट वितरित कर शिक्षा के नए सफर के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी दिनेश झा ने कहा कि शिक्षा बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की सबसे मजबूत नींव है। शासन का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि सरकार निःशुल्क शिक्षा,पाठ्यपुस्तकें, छात्रावास,छात्रवृत्ति,साइकिल सहित अनेक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है,ताकि दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे भी डॉक्टर,इंजीनियर,प्रशासनिक अधिकारी और अन्य क्षेत्रों में अपनी पहचान बना सकें।

न्यायालय सक्षम प्राधिकृत अधिकारी एवं उप वनमण्डलाधिकारी, उपवनमण्डल-सूरजपुर,जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

सूचना

एतद् द्वारा अधोलिखित वाहन के सर्व संबंधितों एवं हितबद्धों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 20.08.2024 को वनपरिक्षेत्र- सूरजपुर अंतर्गत निम्नलिखित वाहन को अवैध रुप से ईमारती लकड़ी परिवहन करते हुये पाये जाने पर जप्त किया जाकर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा - 52,33,छत्तीसगढ़ वनोपज व्यापार (विनियम) अधिनियम 1969 की धारा 5 15, 16 के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 12356/22 दिनांक 20.08.2024 पंजीबद्ध किया गया है।

जप्त वनोपज एवं वाहन का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है-

क्रं	वाहन का प्रकार एवं वाहन क्रमांक	इंजिन क्रमांक	चेसिस क्रमांक	जप्त वनोपज की मात्रा
1	महिन्द्रा बोलेरो पिकप पंजीयन क्रमांक CG-15 AC-3740	GHE1E36326	MA1ZN2GHKE1E45810	साल प्रजाति लट्ठा 8 नग = 1.391 घ.मी.

उक्त जप्तशुदा वाहन एवं वनोपज के राजसात की कार्यवाही सक्षम प्राधिकृत अधिकारी एवं उप वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर, जिला- सूरजपुर (छ.ग.) के न्यायालय में विचाराधीन है।

उक्त जप्तशुदा महिन्द्रा बोलेरो पिकप पंजीयन क्रमांक - CG15 AC-3740 इंजिनं क्रमांक GHE1E36326 चेसिस क्रमांक MA1ZN2GHKE1E45810 के अधिहरण के कार्यवाही के विरुद्ध यदि किसी व्यक्ति / संस्था को कोई स्वामित्व प्रस्तुत करना हो तो वे प्रकाशन तिथी के 15 दिवस या इसके पूर्व इस न्यायालय में कार्यालयीन समय पर उपस्थित होकर अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उचित दस्तावेजों सहित अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के बाद कोई आवेदन मान्य नहीं की जावेगी एवं प्रकरण में राजसात की एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये आदेश पारित कर दी जावेगी ।

सक्षम प्राधिकृत अधिकारी
एवं उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल - सूरजपुर

जी0नं0 -262702018/2

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा.

रा.प्र.क्र./अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण जसराज सिंह बाबरा, नीतराज सिंह बाबरा आ.स्व. जोगराज बाबरा, निवासी देवीगंज रोड़ अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदकगण के पिता स्व0 जोगराज बाबरा के संयुक्त स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अम्बिकापुर, मोहल्ला-देवीगंज रोड़ स्थित नजूल भूमि प्लॉट नंबर 1163/1 रकबा 0.33 1/4 एकड़ भूमि है। सह भूधारक जोगराज बाबरा की मृत्यु दिनांक 10.05.2017 को हो गई है। अतः उनके मृत्यु उपरांत उक्त आवेदित भूमि से उनका नाम विलोपित कर स्वयं के नाम से आवेदित भूमि का नामांतरण किये जाने हेतु आवेदकगण द्वारा मृत्तक जोगराज बाबरा के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-19/07/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक- 09/06/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सील

नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

दो साल,दो नाबालिग,दो आत्महत्याएं...क्या व्यवस्था और समाज की संवेदनशीलता भी दो हिस्सों में बंट गई?

2024 में पुलिस पर प्रताड़ना के आरोप,2026 में दुकान संचालकों पर कार्रवाई की मांग...आखिर समाज का पैमाना अलग क्यों?

पटना से बैकुंठपुर तक : दो नाबालिगों की मौत ने खड़े किए एक जैसे सवाल,क्या न्याय की आवाज भी व्यक्ति देखकर उठती है?

दो घटनाएं,एक सवाल : नाबालिगों की मौत पर क्या समाज और व्यवस्था का रवैया एक जैसा रहा?

एक मामले में पुलिस पर आरोप, दूसरे में दुकान संचालकों पर...दो साल में दो आत्महत्याओं ने खोल दी व्यवस्था की परतें

नाबालिगों की दो मौतें,दो अलग प्रतिक्रियाएं...क्या न्याय का पैमाना भी बदल जाता है?

दो साल में दो नाबालिगों ने गंवाई जान,क्या संवेदनशीलता और जवाबदेही भी दो हिस्सों में बंट गई?

पटना से बैकुंठपुर तक : क्या कोरिया में नाबालिगों से जुड़े मामलों से व्यवस्था ने सबक लिया?

वर्ष 2024 में पुलिस पर लगे कथित प्रताड़ना के आरोपों से लेकर वर्ष 2026 में दुकान संचालकों पर दर्ज एफआईआर तक—दोनों घटनाओं ने पुलिस, समाज और न्याय व्यवस्था की संवेदनशीलता पर गंभीर बहस छेड़ दी है...

-रवि सिंह-

कोरिया/बैकुंठपुर,12 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

किसी भी सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने सबसे कमजोर और सबसे असहाय व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करता है,जब बात नाबालिग बच्चों की हो,तो यह जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, कोरिया जिले में पिछले दो वर्षों के भीतर नाबालिगों की आत्महत्या से जुड़े दो ऐसे मामले सामने आए, जिन्होंने पूरे जिले को झकझोर दिया, दोनों घटनाएं अलग-अलग समय और परिस्थितियों में हुई, दोनों की कानूनी स्थिति अलग है,लेकिन दोनों घटनाओं में एक समानता दिखाई देती है दोनों मामलों में आत्महत्या से पहले कथित मानसिक प्रताड़ना के आरोप सामने आए,यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या समाज और व्यवस्था ने दोनों मामलों को समान संवेदनशीलता से देखा? या फिर आरोप किस पर हैं, इसके आधार पर प्रतिक्रिया बदल गई?

पहला मामला: वर्ष 2024,पटना थाना क्षेत्र और नाबालिग की आत्महत्या- 20 नवंबर 2024 को पटना थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के गुम होने के बाद उसका शव बरामद हुआ,उस मामले की जांच के दौरान पुलिस एक अन्य 14 वर्षीय नाबालिग को पूछताछ के लिए थाने लेकर आई,बाद में मृतक नाबालिग के पिता द्वारा राज्यपाल,राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग सहित विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं को दिए गए आवेदन में आरोप लगाया गया कि उनके पुत्र के साथ थाने में मारपीट, धमकी और मानसिक प्रताड़ना की गई,आवेदन में यह भी कहा गया कि पूछताछ के बाद शाम को उसे छोड़ दिया गया, लेकिन अगले ही दिन उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, परिजनों का आरोप था कि पुलिस के व्यवहार और मानसिक दबाव के कारण नाबालिग ने यह कदम उठाया,उस समय इस मामले को लेकर कई समाचार प्रकाशित हुए, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे और बाल अधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा भी सामने आया, हालांकि पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई और मूल हत्या प्रकरण में चालान भी पेश किया,लेकिन परिजनों द्वारा लगाए गए प्रताड़ना के आरोपों पर आज तक कोई स्पष्ट सार्वजनिक निष्कर्ष सामने नहीं आया।

दूसरा मामला : वर्ष 2026,नाबालिग आदिवासी छात्रा की आत्महत्या-लगभग दो वर्ष बाद 7 जुलाई 2026 को बैकुंठपुर में एक और नाबालिग की आत्महत्या ने पूरे जिले को हिला दिया, एफआईआर के अनुसार नाबालिग आदिवासी छात्रा पर एक दुकान में चोरी का आरोप लगाया गया,शिकायत में आरोप है कि दुकान संचालकों ने उसे घंटों बैठाकर रखा, मानसिक दबाव बनाया,धन की मांग की और उसकी स्कूटी रोक ली, अगले दिन छात्रा ने आत्महत्या कर ली,इस मामले में तीन दिन बाद अपराध दर्ज हुआ और आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया,इसके बाद पूरे जिले में व्यापक जनआंदोलन देखने को मिला,पुलिस परिवार स्वयं सड़क पर उतरा, राजनीतिक दल सक्रिय हुए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई।

दोनों घटनाएं अलग,लेकिन सवाल एक जैसे- यह स्पष्ट है कि दोनों मामलों की परिस्थितियां अलग थीं, एक मामले में आरोप पुलिस पर लगे, दूसरे मामले में आरोप निजी दुकान संचालकों पर लगे, लेकिन यदि दोनों मामलों की सामाजिक प्रतिक्रिया को देखा जाए,तो कई लोगों के मन में प्रश्न उठ रहे हैं, क्या वर्ष 2024 में भी उतनी ही ताकत से समाज पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर सामने आया था? क्या तब भी हजारों लोग सड़क पर उतरे थे? क्या तब भी उतना ही दबाव बनाया गया था जितना आज बनाया जा रहा है? यही वे प्रश्न हैं जिन पर चर्चा हो रही है।

क्या समाज भी व्यक्ति देखकर तय करता है कि किसके लिए आवाज उठानी है?- यह प्रश्न केवल पुलिस या प्रशासन से जुड़ा नहीं है,यह समाज से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है,यदि किसी मामले में आरोपी पुलिसकर्मी हो,तो क्या समाज उतनी मजबूती से खड़ा होता है? और यदि आरोपी कोई निजी व्यक्ति या व्यापारी हो, तो क्या प्रतिक्रिया बदल जाती है? लोकतंत्र में न्याय का सिद्धांत यही कहता है कि पीड़ित की पीड़ा बराबर होती है,प्रताड़ना यदि किसी पुलिसकर्मी ने की हो तो भी उतनी ही गंभीर है,और यदि किसी निजी व्यक्ति ने की हो तो भी उतनी ही गंभीर है।

क्या दोनों मामलों में एक जैसी जवाबदेही तय हुई?- वर्ष 2024 के मामले में परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि नाबालिग को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया,यदि यह आरोप गलत थे तो जांच में सार्वजनिक रूप से स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए थी,यदि आरोप सही थे तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी,आज भी कई लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि उस मामले में आखिर कार्रवाई किस स्तर तक पहुंची।

नाबालिग आदिवासी छात्रा प्रकरण में तेजी से बढ़ा सामाजिक दबाव- इसके विपरीत नाबालिग आदिवासी छात्रा मामले में समाज बड़ी संख्या में सामने आया, पुलिस परिवार स्वयं सड़क पर उतर आया, राजनीतिक दल सक्रिय हो गए,पूर्व विधायक, जनप्रतिनिधि,सामाजिक संगठन और स्थानीय नागरिक लगातार कार्रवाई की मांग करते रहे,यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की सकारात्मक तस्वीर भी है कि समाज न्याय की मांग कर रहा है,लेकिन इसी के साथ यह तुलना भी सामने आ रही है कि क्या वर्ष 2024 में भी यही संवेदनशीलता दिखाई गई थी?

क्या कानून सबके लिए समान है?-

यह पूरा घटनाक्रम एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न भी खड़ा करता है, यदि किसी निजी व्यक्ति पर यह आरोप लगता है कि उसकी कथित प्रताड़ना, धमकी या मानसिक दबाव के कारण किसी ने आत्महत्या की, तो पुलिस प्रथम दृष्टया अपराध दर्ज कर जांच शुरू करती है, ऐसे में स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि यदि किसी मामले में पुलिसकर्मियों पर भी प्रताड़ना या मानसिक दबाव के ऐसे ही आरोप लगाए जाएं और आरोप हो कि उसी के कारण किसी व्यक्ति ने आत्महत्या की, तो क्या उस स्थिति में भी समान कानूनी कसौटी पर जांच और आवश्यक होने पर अपराध दर्ज नहीं होना चाहिए? लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून के शासन का मूल सिद्धांत यही है कि कानून की नजर में सभी समान हैं, इसलिए ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच, समान मानदंड और जवाबदेही ही न्याय व्यवस्था पर जनता के विश्वास को मजबूत कर सकती है।

दोहरा चरित्र या अलग परिस्थितियां?-कई लोग इसे समाज का दोहरा चरित्र कह रहे हैं,वहीं कुछ लोगों का तर्क है कि दोनों मामलों की परिस्थितियां अलग थीं,इसलिए प्रतिक्रिया भी अलग रही,सच्चाई जो भी हो,लेकिन यह बहस अब सार्वजनिक हो चुकी है।

सबसे बड़ा सवाल—क्या हर नाबालिग बराबर है?- दोनों मामलों से सबसे बड़ा प्रश्न यही निकलकर सामने आता है क्या हर नाबालिग के अधिकार बराबर हैं? क्या हर बच्चे की मौत समान संवेदनशीलता की हकदार है? क्या न्याय की मांग व्यक्ति देखकर होनी चाहिए? या केवल इस आधार पर कि एक बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा?

पुलिस और समाज—दोनों के लिए आत्ममंथन का समय- इन दोनों घटनाओं ने केवल पुलिस व्यवस्था को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को आईना दिखाया है,पुलिस के लिए यह आवश्यक है कि नाबालिगों से जुड़े मामलों में पूछताछ, हस्तक्षेप और संकट प्रबंधन के दौरान अधिक संवेदनशील और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाए, वहीं समाज को भी यह तय करना होगा कि उसकी आवाज किसी व्यक्ति, संस्था या पद के आधार पर नहीं, बल्कि न्याय के सिद्धांत पर उठनी चाहिए।

न्याय का पैमाना एक होना चाहिए-यह लेख किसी मामले में दोष तय करने का प्रयास नहीं है, दोनों मामलों में अंतिम सत्य जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही सामने आएगा, लेकिन दोनों घटनाओं ने एक ऐसा सवाल जरूर छोड़ दिया है,जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, यदि एक नाबालिग की मौत पर पूरा समाज सड़क पर उतरता है और दूसरी घटना में अपेक्षाकृत खामोश रहता है,तो यह आत्ममंथन का विषय है,कानून का शासन तभी मजबूत होगा जब न्याय का पैमाना हर व्यक्ति के लिए समान होगा, चाहे आरोप किसी पुलिसकर्मी पर हों, किसी प्रभावशाली व्यक्ति पर हों या किसी सामान्य नागरिक पर—जवाबदेही,संवेदनशीलता और निष्पक्षता का स्तर एक जैसा होना चाहिए, तभी समाज यह विश्वास कर पाएगा कि न्याय व्यक्ति देखकर नहीं, बल्कि तथ्य और कानून देखकर किया जाता है।

राजस्थान से लौटते वक्त अनूपपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा मुख्य आरोपी,नाबालिग छात्रा आत्महत्या मामले में भेजा गया जेल

कोरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई...दो फरार आरोपियों की तलाश तेज

पीड़ित परिवार को एससी-एसटी एक्ट के तहत 4.12 लाख की पहली किश्त

-संवाददाता-

कोरिया/बैकुंठपुर,12 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिले के बहुचर्चित नाबालिग आदिवासी छात्रा आत्महत्या प्रकरण में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है,घटना के बाद से फरार चल रहे मुख्य आरोपी विनोद वैद्य को पुलिस ने राजस्थान से लौटते समय मध्यप्रदेश के अनूपपुर में गिरफ्तार कर लिया,गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोरिया लाकर न्यायालय में पेश किया गया,जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, वहीं मामले के दो अन्य नामजद आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। घटना के बाद से चल रही थी तलाश- पुलिस के अनुसार नाबालिग छात्रा की आत्महत्या के बाद दर्ज हुए प्रकरण में तीनों आरोपी फरार हो गए थे,मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रवि कुमार कुर्रे ने प्रत्येक आरोपी की गिरफ्तारी में सहयोग करने वाले व्यक्ति के लिए 5-5 हजार के इनाम की घोषणा की थी,लगातार दबिश और तकनीकी निगरानी के बीच पुलिस को सूचना मिली कि मुख्य आरोपी राजस्थान से लौट रहा है, इसके बाद पुलिस ने अनूपपुर में घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

प्रताड़ना के आरोप के बाद हुई थी आत्महत्या-मामला बैकुंठपुर निवासी 17 वर्षीय आदिवासी छात्रा की आत्महत्या से जुड़ा है, परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि छात्रा एक प्रतिष्ठान (आईसी मार्ट) गई थी,जहां उस पर चोरी का आरोप लगाकर कथित रूप से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, शिकायत में यह भी आरोप है कि उससे लिखवाया गया कि उसने चोरी की है, आर्थिक दबाव बनाया गया और उसकी स्कूटी भी रोक ली गई,परिजनों का आरोप है कि कथित प्रताड़ना और सार्वजनिक अपमान से आहत होकर छात्रा ने घर लौटने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली,इन आरोपों की सत्यता का निर्धारण पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद होगा।

गंभीर धाराओं में दर्ज है मामला...

शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। घटना के बाद जिलेभर में विरोध प्रदर्शन हुए और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठी।

पीड़ित परिवार को मिली आर्थिक सहायता...

पुलिस अधीक्षक रवि कुमार कुर्रे ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत पीड़ित परिवार को 4 .12 लाख की प्रथम किश्त आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की गई है। आगे की सहायता भी नियमानुसार उपलब्ध कराई जाएगी।

दो आरोपी अब भी फरार...

पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले में नामजद जगत वैद्य और दीपक वैद्य अभी भी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, पुलिस का कहना है कि शेष आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा।

जांच जारी, आगे की कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर...

मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को मामले में महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है,पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के आधार पर मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है, विवेचना में सामने आने वाले साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, फिलहाल पूरे जिले की नजर शेष दो आरोपियों की गिरफ्तारी और जांच के अंतिम निष्कर्ष पर टिकी हुई है।

खेत से खुशियों तक : सरगुजा-कोरिया में 'छेवर' का उत्सव,जब श्रमिक बहनें किसान भाइयों की कलाई पर बांधती हैं 'धान की राखी'

- श्रम और स्नेह का अनूठा संगम : जहाँ पसीने की खुशबू और रिश्तों की मिठास एक हो जाती है...
- सिर्फ पारिश्रमिक नहीं,सम्मान का पर्वः जहाँ श्रम का मोल प्रेम,विश्वास और अपनत्व से चुकाया जाता है...

राजन पाण्डेय

कोरिया,12 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा और कोरिया अंचल की पहचान केवल धान के कटोरे के रूप में ही नहीं, बल्कि अपनी जीवंत लोक परंपराओं और मानवीय मूल्यों के कारण भी है,यहां खेती केवल आजीविका का साधन नहीं,बल्कि संस्कृति,रिश्तों और सामूहिक श्रम का उत्सव है, ऐसी ही एक अनूठी और भावनात्मक परंपरा है 'छेवर',जो धान की रोपाई पूरी होने के बाद मनाई जाती है,यह पर्व खेतों में बहाए गए पसीने का सम्मान तो है ही,साथ ही किसान और खेतिहर श्रमिकों के बीच आत्मीय रिश्तों की मिसाल भी प्रस्तुत करता है,धान की रोपाई वर्षभर के सबसे कठिन कृषि कार्यों में गिनी जाती है,तेज धूप,लगातार बारिश,घुटनों तक कीचड़ और घंटों झुककर काम करने के बावजूद किसान और श्रमिक मिलकर भविष्य की फसल की नींव रखते हैं, जब रोपाई का अंतिम दिन आता है,तब पूरे उत्साह के साथ 'छेवर' मनाया जाता है। यह केवल काम खत्म होने का अवसर नहीं, बल्कि सामूहिक श्रम की सफलता का उत्सव होता है।

श्रमिकों के सम्मान का दिन...

छेवर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस दिन किसान अपने साथ काम करने वाले श्रमिकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें निर्धारित मजदूरी के साथ विशेष सम्मान दिया जाता है,कई स्थानों पर सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है,तो कहीं अतिरिक्त पारिश्रमिक या उपहार देकर उनके योगदान का सम्मान किया जाता है,इस परंपरा में मालिक और मजदूर का संबंध औपचारिक नहीं रहता, बल्कि परिवार जैसा अपनापन दिखाई देता है।

जब धान के पौधों से बनती है 'धान की राखी'-छेवर का सबसे भावुक और सांस्कृतिक रूप तब सामने आता है, जब खेतों में काम करने वाली श्रमिक बहनें किसान भाइयों की कलाई पर धान के कोमल पौधों (कंसों) से बनी 'धान की राखी' बांधती हैं, यह राखी केवल रक्षा का प्रतीक नहीं, बल्कि खेत, फसल,प्रकृति और आपसी विश्वास के अटूट संबंध का संदेश देती है,राखी बांधते समय बहनों के चेहरे पर संतोष और आत्मीयता का भाव होता है,जबकि किसान भाई भी पूरे सम्मान के साथ इस परंपरा को निभाते हैं,यह दृश्य बताता है कि खेतों में साथ काम करने वाले लोग केवल श्रमिक और किसान नहीं,बल्कि एक-दूसरे के सुख-दुख के सहभागी भी हैं।

संस्कृति,संवेदना और सामाजिक समरसता का संदेश

आज जब आधुनिक जीवनशैली में रिश्ते औपचारिक होते जा रहे हैं,तब सरगुजा और कोरिया की यह परंपरा समाज को यह संदेश देती है कि मेहनत का सम्मान,श्रमिकों के प्रति आदर और भाईचारे की भावना ही किसी भी समाज की वास्तविक पूंजी है,यहां श्रम का मूल्य केवल धन से नहीं, बल्कि सम्मान,प्रेम और विश्वास से चुकाया जाता है, 'छेवर' यह भी सिखाता है कि खेती केवल अन्न उत्पादन की प्रक्रिया नहीं,बल्कि सामाजिक समरसता का आधार भी है, खेतों में बोए गए धान के पौधों के साथ-साथ यहां विश्वास,अपनापन और आत्मीय रिश्तों के बीज भी अंकुरित होते हैं।

लोक संस्कृति की अमूल्य धरोहर

लोक संस्कृति के जानकारों का मानना है कि ऐसी परंपराएं गांवों की सामाजिक एकजुटता को मजबूत करती हैं,धान की राखी इस बात का प्रतीक है कि अन्न केवल खेतों में नहीं,बल्कि प्रेम,सहयोग और परस्पर सम्मान की भूमि पर भी उगता है,बदलते समय में भी यदि यह परंपरा जीवित है,तो यह छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक चेतना का प्रमाण है,वास्तव में, 'छेवर' केवल धान की रोपाई पूर्ण होने का उत्सव नहीं, बल्कि श्रम,सम्मान,भाईचारे और संस्कृति का ऐसा पर्व है,जो यह संदेश देता है कि जब तक किसान और श्रमिकों के बीच यह आत्मीय रिश्ता कायम रहेगा,तब तक छत्तीसगढ़ की धरती केवल धान ही नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और मानवीय मूल्यों की भी समृद्ध फसल उगाती रहेगी।

नजूल भूमि पर अवैध निर्माण का आरोप,सर्व आदिवासी समाज ने एसडीएम से की तत्काल कार्रवाई की मांग

-संवाददाता-
पटना/कोरिया,12 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
नगर पंचायत पटना के वार्ड क्रमांक 09 में कथित रूप से नजूल भूमि पर किए जा रहे निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है, सर्व आदिवासी समाज, जिला-कोरिया ने इस मामले में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),बैकुंठपुर को लिखित शिकायत सौंपते हुए आरोप लगाया है कि वार्ड क्रमांक 09 के पार्षद राजेश सोनी द्वारा बाज़ारपारा, पटना स्थित नजूल भूमि पर मकान का निर्माण कराया जा रहा है,संगठन ने मामले की तत्काल जांच कर अवैध निर्माण पर रोक लगाने तथा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। सर्व आदिवासी समाज की ओर से दिए गए आवेदन में कहा गया है कि संबंधित भूमि नजूल श्रेणी की है, जिस पर निजी निर्माण कराया जाना नियमों के विपरीत है, शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस संबंध में नगर पंचायत पटना के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) को फोन के माध्यम से पहले ही सूचना दी जा चुकी थी,लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य लगातार जारी है,संगठन का आरोप है कि प्रशासनिक स्तर पर समय रहते कार्रवाई नहीं किए जाने से नियमों की अनदेखी हो रही है,शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यदि नजूल भूमि पर निर्माण कार्य बिना वैधानिक अनुमति के हो रहा है तो इससे न केवल सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बढ़ेगा,बल्कि भविष्य में ऐसे मामलों को बढ़ावा भी मिलेगा। इसलिए प्रशासन को निष्पक्ष जांच कर यह स्पष्ट करना चाहिए कि संबंधित निर्माण विधिसम्मत है अथवा नहीं, सर्व आदिवासी समाज ने अपने आवेदन में एसडीएम से मांग की है कि पूरे मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए तथा जांच के बाद यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए, संगठन ने यह भी कहा है कि सरकारी भूमि की सुरक्षा प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही सार्वजनिक हित के विपरीत होगी, इधर, शिकायत सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर भी इस मामले की चर्चा तेज हो गई है, लोगों का मानना है कि यदि सरकारी अथवा नजूल भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण किया जा रहा है तो उसकी वैधता की जांच आवश्यक है, ताकि भविष्य में भूमि विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो, हालांकि, समाचार लिखे जाने तक इस मामले में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अथवा नगर पंचायत पटना की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, इसी प्रकार शिकायत में जिन पार्षद राजेश सोनी का उल्लेख किया गया है,उनका पक्ष भी प्राप्त नहीं हो सका है,उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। प्रशासन द्वारा शिकायत पर क्या कार्रवाई की जाती है और जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं, इस पर अब स्थानीय नागरिकों और शिकायतकर्ताओं की निगाहें टिकी हुई हैं।

शिक्षा व्यवस्था पर संलग्नीकरण का ग्रहण! दूसरे विभागों में अटके कर्मचारी, स्कूलों में स्टाफ का संकट गहराया

डीईओ का बड़ा पत्र उजागर : शासन के आदेश के बाद भी नहीं लौटे कर्मचारी,कलेक्टर से तत्काल भारमुक्त करने की मांग...

-संवाददाता-
खड़गवां/एमसीबी,12 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले की शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर कर्मचारियों की कमी के संकट से जूझती नजर आ रही है,इस बार यह मुद्दा किसी संगठन या जनप्रतिनिधि ने नहीं, बल्कि स्वयं जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ने उठाया है, कलेक्टर को भेजे गए आधिकारिक पत्र में डीईओ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि शिक्षा विभाग के कई शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारी वर्षों से अन्य विभागों में संलग्न (अटैच) हैं, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संलग्नीकरण समाप्त करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने के बावजूद अब तक इन कर्मचारियों की मूल विभाग में वापसी नहीं हुई है, जिसका सीधा असर जिले की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है, डीईओ के पत्र के अनुसार जिले के अनेक विद्यालय, विकासखंड शिक्षा कार्यालय और जिला शिक्षा कार्यालय कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं, जिन कर्मचारियों को विद्यार्थियों की पढ़ाई, परीक्षा, प्रशासनिक कार्य और शैक्षणिक गतिविधियों में योगदान देना चाहिए था, वे अन्य विभागों में सेवाएं दे रहे हैं, इससे शिक्षा विभाग के नियमित कार्य प्रभावित हो रहे हैं और उपलब्ध कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ गया है।

शिक्षा स्तर पर भी पड़ रहा असर-पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में एमसीबी जिले का शैक्षणिक प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा,कई विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी के कारण शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हुई, प्रशासनिक कार्यों का बोझ भी सीमित कर्मचारियों पर आ जाने से शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, विभाग का मानना है कि यदि संलग्न कर्मचारियों की शीघ्र वापसी होती है तो विद्यालयों में मानव संसाधन की कमी दूर होगी और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकेगा।

कलेक्टर से तत्काल हस्तक्षेप की मांग- जिला शिक्षा अधिकारी ने कलेक्टर से अनुरोध किया है कि अन्य विभागों में संलग्न सभी शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को तत्काल भारमुक्त कर उनके मूल विभाग में भेजने के निर्देश जारी किए जाएं। उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए यह कदम आवश्यक है।

शासन के आदेश के बाद भी क्यों जारी है संलग्नीकरण?-सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सामान्य प्रशासन विभाग पहले ही संलग्नीकरण समाप्त करने के निर्देश जारी कर चुका है,तब भी कई कर्मचारी वर्षों से अन्य विभागों में कैसे कार्यरत हैं? क्या संबंधित विभागों ने शासन के आदेशों का पालन नहीं किया, या फिर किसी प्रशासनिक संरक्षण के कारण यह व्यवस्था जारी रही? यदि ऐसा है तो इसकी जवाबदेही किसकी तय होगी?

विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा मामला

विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा विभाग में कर्मचारियों की कमी का सबसे बड़ा नुकसान विद्यार्थियों को उठाना पड़ता है,शिक्षक और कर्मचारी यदि अपने मूल दायित्वों से हटकर अन्य विभागों में कार्य करेंगे तो स्कूलों में शिक्षण,परीक्षा,रिकॉर्ड संधारण और प्रशासनिक कार्य प्रभावित होना स्वाभाविक है,ऐसे में सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के प्रयास भी अधूरे रह सकते हैं।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छत्तीसगढ़)
E-mail : deo.mcb.cg@gmail.com
Ph. 07771-299999
/FILE nO:. rule-3017/2/2025-GAD-6
संलग्न- राजस्व विभाग में संलग्न कर्मचारियों की सूची।

उठ रहे अहम सवाल...

शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद शिक्षा विभाग के कर्मचारी अब तक मूल विभाग में क्यों नहीं लौटे? वर्षों से संलग्नीकरण किन परिस्थितियों और किसके संरक्षण में जारी रहा? क्या अब कलेक्टर इस मामले में सख्त निर्णय लेते हुए सभी कर्मचारियों को तत्काल भारमुक्त करेंगे? क्या कर्मचारियों की वापसी से एमसीबी जिले की गिरती शैक्षणिक गुणवत्ता में वास्तविक सुधार देखने को मिलेगा? अब निगाहें जिला प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं, यदि डीईओ की अनुशंसा पर समयबद्ध कार्रवाई होती है,तो इससे न केवल शिक्षा विभाग में कर्मचारियों की कमी दूर होगी, बल्कि जिले की शिक्षण व्यवस्था को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।

आवास योजना में अनियमितता और मजदूरी भुगतान का मामला उठा, जांच की मांग

ऑल मीडिया प्रेस एसोसिएशन के जिला पब्लिक सचिव ने कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ के नाम जनपद सीईओ कुसमी को सौंपा आवेदन

-संवाददाता-
कुसमी/बलरामपुर,12 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
जनपद पंचायत कुसमी अंतर्गत ग्राम पंचायत इदरी कला में महात्मा गांधी नरेगा के तहत तालाब निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के मजदूरी भुगतान तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में कथित अनियमितता का मामला सामने आया है। इन दोनों मामलों की जांच एवं कार्रवाई की मांग को लेकर ऑल मीडिया प्रेस एसोसिएशन,बलरामपुर के जिला पब्लिक सचिव कैफ अली ने कलेक्टर बलरामपुर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नाम जनपद पंचायत कुसमी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आवेदन सौंपा है। आवेदन के अनुसार, ग्राम पंचायत इदरी कला में तालाब निर्माण कार्य में कार्यरत महिला मजदूरों को उनकी पूरी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। आरोप है कि मजदूरों को केवल आधी मजदूरी दी गई, जबकि शेष राशि का अब तक भुगतान नहीं हुआ है। इससे मजदूरों में नाराजगी है और वे लंबे समय से अपने बकाया भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े मामले में भी गंभीर अनियमितता का आरोप लगाया गया है। आवेदन में कहा गया है कि वर्ष 2023-24 में योजना के हितग्राही राजेंद्र बड़ा के लिए स्वीकृत आवास की राशि कथित रूप से रोजगार सहायक एवं सरपंच की मिलीभगत से गांव के ही निवासी जगेश्वर के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी गई और राशि का आहरण कर लिया गया। शिकायतकर्ता ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा हितग्राही को न्याय दिलाने की मांग की है। ऑल मीडिया प्रेस एसोसिएशन के जिला पब्लिक सचिव कैफ अली ने मांग की है कि दोनों मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों एवं संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा मजदूरों का बकाया भुगतान और आवास योजना के वास्तविक हितग्राही को उसका अधिकार सुनिश्चित कराया जाए।

सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर बलरामपुर थाना परिसर में हुआ एकता वृक्षारोपण

-संवाददाता-
बलरामपुर,12 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर रविवार को बलरामपुर थाना परिसर में 'एकता वृक्षारोपण कार्यक्रम' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देना रहा। इस अवसर पर थाना परिसर में जनप्रतिनिधियों एवं पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति में पौधरोपण किया गया। उपस्थित जनों ने पौधों के संरक्षण का संकल्प लेते हुए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद बलरामपुर के अध्यक्ष लोधी राम एक्का, उपाध्यक्ष दिलीप सोनी, पार्षद राकेश सिंह, पूर्व पार्षद विनय यादव तथा भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री भानु दीक्षित विशेष रूप से उपस्थित रहे। थाना स्टाफ ने भी उत्साहपूर्वक वृक्षारोपण अभियान में सहभागिता निभाई। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। उनकी जयंती पर आयोजित वृक्षारोपण अभियान पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ उनके आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने का सार्थक प्रयास है। उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने नागरिकों से भी अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने की अपील की।

हर लड़के की धड़कन में बसता है 37 साल पुराना ये मखमली गाना

अनुराधा पौडवालऔर कुमार सानू की आवाज ने बनाया अमर

अनुराधा पौडवाल ने हिंदी सिनेमा में कई रोमांटिक गीत गाए हैं। 1989 में उन्होंने कुमार सानू के साथ एक गाना गाया जो आज भी हर किसी की जुबान पर चढ़ा रहता है।

अनुराधा पौडवाल को ने हिंदी सिनेमा में एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर कदम रखा। शुरुआत में उन्होंने कई भजन भी गाए जिसकी वजह से उन्हें भजन क्वीन का टैग मिला। हालांकि अनुराधा जी को ये बात बहुत बुरी लगी क्योंकि वो खुद को किसी जॉनर में बांधना नहीं चाहती थीं।एक इंटव्यू में अनुराधा पौडवाल ने बताया कि इसके बाद वो बहुत रोई भी थीं। भजन के अलावा अनुराधा पौडवाल ने कई फिल्मों के लिए रोमांटिक और मेलोडिक गाने गाए हैं जिनको अपार सफलता मिली। उन्होंने 80 और 90 के दशक में कई सुपरहिट हिंदी फिल्मों के लिए सदाबहार गीत गाए।

अभी भी नहीं बदली सिंगर की आवाज

कहा तो ये तक जाता है कि कई सिंगर की आवाज समय के साथ बदल गई लेकिन अनुराधा जी की आवाज में आज भी वहीं 16 साल की लड़की की आवाज वाली खनक है जो वो अपनी यंग ऐज में गाया करती थीं। आज आपको अनुराधा जी की आवाज में सजे ऐसे ही एक रोमांटिक गीत के बारे में बताएंगे जो हर लड़के के दिल की आवाज बना।

90 दशक के दशक में सबकी जुबान पर बस एक गाना

90 दशक के दशक में हर एक लड़का दीवाना घूमता था और अपने प्यार का इजहार करने के लिए उन्हीं के गीत गाता था। हम बात कर रहे हैं साल 1989 में आई फिल्म आशिकी के गाने **धीरे-धीरे से मेरी जिंदगी में आना,धीरे-धीरे से दिल को चुराना** की। ये गीत अनु अग्रवाल और राहुल रॉय पर फिल्माया गया है। इसे कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल ने अपनी आवाज से सजाया था। रानी मलिक ने इसके लिरिक्स लिखे थे।

टी सीरीज को खूब मिली पॉपुलैरिटी

वैसे तो इस फिल्म के सारे ही गाने बहुत हिट थे लेकिन धीरे-धीरे मेरी जिंदगी में आना की बात ही अलग थी। आशिकी एक बहुत बड़ी म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर बनकर सामने आई। संगीतकार जोड़ी नदीम-श्रवण और गायक कुमार सानू के लिए यह फिल्म मील का पत्थर साबित हुई। इसके गानों ने इतनी सफलता पाई कि उस साल फिल्म के कैसेट्स की बिक्री 2 करोड़ (20 मिलियन) से भी अधिक हुई थी। इसने टी-सीरीज को भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनियों में से एक बना दिया था। वहीं मूवी के स्टार्स राहुल रॉय और अनु अग्रवाल रातों-रात सनसनी बन गए। सिनेमाघरों में फैंस राहुल रॉय के बालों के स्टाइल और उनके आशिकाना अंदाज के दीवाने हो गए थे।

भाई तेरा स्टार है का मजेदार ट्रेलर हुआ जारी
हीरो बनकर हंसाने आए राघव जुयाल

किल और बैड्स ऑफ बॉलीवुड जैसी फिल्मों में अपनी गंभीर और दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाने के बाद राघव जुयाल अब दर्शकों को हंसाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मेकर्स ने उनकी आगामी फिल्म भाई तेरा स्टार है का शानदार ट्रेलर रिलीज कर दिया है। इस ट्रेलर में राघव के किरदार अजय सिंह की एक बेहद अनोखी,अतरंगी और मजेदार दुनिया की झलक देखने को मिल रही है,जिसने फैंस के बीच फिल्म को लेकर उत्सुकता काफी बढ़ा दी है। इस बार वह एक फुल-ऑन कॉमिक एंटरटेनर के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं।

यह फिल्म पूरी तरह से एक पारिवारिक मनोरंजन पैकेज है। ट्रेलर की शुरुआत ही एक बेहद मजेदार डायलॉग से होती है, एक एक्टर का सबसे बड़ा टैलेंट होता है अपनी ही बकवास पर यकीन करना। इसके बाद से ही पूरे ट्रेलर में बड़े-बड़े सपने, जबरदस्त कन्फ्यूजन और पेट खोलकर हंसाने वाले सीन्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिल्म में राघव जुयाल की कॉमिक टाइमिंग के साथ-साथ संजय कपूर, बरखा सिंह, निहारिका एनएम और चंदन रॉय सान्याल जैसे बेहतरीन कलाकार भी अपनी कॉमेडी से एंटरटेनमेंट का लेवल बढ़ाते नजर आ रहे हैं।

अपने इस नए रोल को लेकर राघव जुयाल काफी उत्साहित हैं। उन्होंने बताया कि अजय सिंह का यह किरदार बहुत ज्यादा ड्रामेटिक,बेबाक और अप्रत्याशित है, जिसे निभाने में उन्हें बेहद मजा आया। वहीं फिल्म के डायरेक्टर विवेक बी अग्रवाल का कहना है कि यह फिल्म खुद को बहुत सीरियसली नहीं लेती और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। उन्होंने राघव की एनर्जी की तारीफ करते हुए कहा कि वे सिनेमाघरों में दर्शकों के रिएक्शन देखने के लिए बेहद उत्सुक हैं।

ट्रेलर के बारे में बात करते हुए राघव जुयाल ने कहा,मुझे पूरा भरोसा है कि यह फिल्म हर उम्र के दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी। मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूं कि सभी लोग अजय सिंह से मिलें। वह एक ऐसा किरदार है जो नाटकीय है, अप्रत्याशित है,बेझिझक है,पूरी तरह ओवर-द-टॉप है और बेहद मनोरंजक भी। इस किरदार को निभाने में मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को भी फिल्म देखते समय उतना ही आनंद आएगा,जितना हमें इसे बनाते समय आया।

निर्देशक विवेक बी अग्रवाल ने कहा,भाई तेरा स्टार है पूरी तरह मनोरंजन का जश्न है। यह फिल्म खुद को जरूरत से ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसमें मज़ेदार किरदार,अप्रत्याशित मोड़ और लगातार मनोरंजन देखने को मिलेगा। राघव ने अजय सिंह के किरदार को अपनी शानदार ऊर्जा और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग से जीवंत बना दिया है। हमें बेहद खुशी है कि आज ट्रेलर दर्शकों के सामने है और अब हम सभी को सिनेमाघरों में फिल्म का आनंद लेते देखने का इंतजार है।

ईस्टवुड पिक्चर्स और इंडियन स्टोरीज 2 के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्देशन विवेक बी अग्रवाल ने किया है। फिल्म की कहानी को सुदीप्तो सरकार और विवेक ने मिलकर लिखा है, जबकि इसके निर्माण की जिम्मेदारी अवंतिका हरि,सुनील रुपानी और विवेक बी. अग्रवाल ने संभाली है। एंटरटेनमेंट और ठहाकों से भरपूर यह फिल्म 30 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है।

शिवांगी जोशी ने पढ़ी थी कुशल टंडन संग उनकी चैट,लॉक अप 2 में श्रेया कालरा ने किया खुलासा

रियलिटी शो लॉक अप सीजन 2 की कंटेस्टेंट श्रेया कालरा ने हाल ही में एक एपिसोड में दावा किया कि एक्ट्रेस और साथी कंटेस्टेंट शिवांगी जोशी ने एक बार उनकी और एक्टर कुशल टंडन की पूरी चैट पढ़ी थी। यह तब हुआ जब कुशल ने उन्हें मैसेज किया था, जबकि वे कथित तौर पर शिवांगी को डेट कर रहे थे। लॉक अप 2 के हालिया एपिसोड में, श्रेया ने साथी कंटेस्टेंट और एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे से बात करते हुए यह बात बताई। उस घटना को याद करते हुए श्रेया ने कहा कि वह शिवांगी के एक टीवी शो के लिए प्रमोशनल वीडियो की शूटिंग कर रही थीं, तभी कुशल ने सोशल मीडिया पर उनसे संपर्क किया।श्रेया ने कहा, शूट के बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया। उस समय मैं किसी को डेट कर रही थी। उस समय कुशल टंडन और शिवांगी जोशी के बीच कुछ चल रहा था। मुझे इसके बारे में पता नहीं था।उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कुशल उन्हें मैसेज करते रहे, लेकिन वह एक कमिटेड रिलेशनशिप में थीं और उन्होंने बातचीत को आगे न बढ़ाने का फैसला किया क्योंकि उन्हें लगा कि बातचीत में कुछ गड़बड़ है।उन्होंने आगे दावा किया, उन्होंने मुझसे बात करना शुरू किया। मुझे कुछ शक हुआ और मैंने बात रोक दी। फिर, शिवांगी और मैं सेट पर मिले और उन्होंने कहा, ओह हाय! हां! उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि तुमने उन्हें फॉलो किया और मैसेज किया। मैंने कहा, एक्सक्यूज मी! मैं किसी आदमी से संपर्क करने वाली पहली इंसान नहीं होऊंगी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं किया है।श्रेया ने कहा कि उन्होंने तुरंत शिवांगी को अपना फोन दे दिया ताकि कोई गलतफहमी हो तो वह दूर हो जाए।

उन्होंने कहा, मैंने उन्हें अपना फोन दे दिया। उन्होंने मेरी पूरी चैट पढ़ी। मैंने कोई फ्लर्ट नहीं किया और न ही कुछ कहा। बातचीत में आगे शिल्पा शिंदे ने पूछा कि क्या मैसेज पढने के बाद शिवांगी रोई थीं। श्रेया ने जवाब दिया, शूट के बाद सेट पर वह रोई थीं। 3-5 महीने बाद, उस लड़के ने एक स्टोरी पोस्ट करके बताया कि उनका ब्रेकअप हो गया है। श्रेया ने आगे दावा किया कि बाद में लॉक अप 2 में साथ रहने के दौरान उन्होंने शिवांगी के पुराने रिश्ते का जिक्र किया ताकि यह समझ सकें कि कपल के बीच क्या गलत हुआ था। हालांकि, उनके अनुसार, शिवांगी ने इस मामले पर चर्चा न करने का फैसला किया और बातचीत । रुख मोड़ दिया।

जो लोग नहीं जानते,उन्हें बता दें कि टीवी शो बरसातें ङ्क मौसम प्यार का में साथ काम करते हुए कुशल टंडन और शिवांगी जोशी के बीच डेटिंग शुरू होने की खबरें आई थीं।दोनों में से किसी ने भी कभी अपने रिश्ते की सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं की, लेकिन खबरों के अनुसार दोनों एक-दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूबे हुए थे।फिलहाल, कुशल अलायंस हाउस में एक कंटेस्टेंट हैं, जबकि शिवांगी लॉक अप 2 में हिस्सा ले रही हैं।

सलमान खान की फ्लॉप एक्शन मूवी : 7 शानदार गानों के बाद भी डूबी फिल्म

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने अपने तीन दशक से ज्यादा लंबे करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। उन्होंने पर्दे पर रोमांस, कॉमेडी और एक्शन के हर रंग को बखूबी जिया है। लेकिन उनकी फिल्मोग्राफी में कुछ ऐसी फिल्में भी शामिल हैं, जिनकी असफलता आज भी दर्शकों और खुद फिल्म मेकर्स को हैरान करती है। एक ऐसा ही दिलचस्प किस्सा सलमान खान की एक पुरानी फिल्म से जुड़ा है, जो लगभग डेढ़ दशक पहले रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी, स्टारकास्ट और सबसे बढ़कर इसका म्यूजिक बेहद लाजवाब था, लेकिन एक गलत फैसले यानी फिल्म के क्लाइमैक्स ने पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया और अच्छी-भली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर महाफ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म के फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वजह इसके डायरेक्टर खुद फिल्म के क्लाइमैक्स को मानते हैं। फिल्म समीक्षकों और दर्शकों का भी यही मानना था कि डायरेक्टर ने फिल्म के अंत में जो ट्विस्ट या सीन डाला, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। दर्शक खुद को उस क्लाइमैक्स से जोड़ नहीं पाए और फिल्म का बंटाधार हो गया। यह फिल्म एक बेहतरीन एक्शन और इमोशनल ड्रामा हो सकती थी, लेकिन इसके आखिरी के कुछ सीन्स ने पूरी कहानी का जायका बिगाड़ दिया। सिनेमाघरों से निकलने के बाद दर्शकों के बीच फिल्म की तारीफ तो थी, लेकिन क्लाइमैक्स को लेकर एक बड़ा असंतोष भी था, जिसने फिल्म के बिजनेस को पूरी तरह से ठप कर दिया।

खेल समाचार

फीफा वर्ल्ड कप 2026 सेमी फाइनल 15 एवं 16 जुलाई को

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का दौर अब सेमीफाइनल में पहुंच चुका है...जहां फ्रांस की भिडंत स्पेन से होगी, फिर अर्जेंटीना और इंग्लैंड आमने-सामने होंगे...

नई दिल्ली,12 जुलाई 2026। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जाने वाली 4 टीमें सामने आ चुकी हैं। क्वार्टर फाइनल के दौर में एक से बढ़कर एक मुकाबले देखने का मिले। सबसे पहले फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से मात दी। फिर स्पेन ने 2-1 से बेल्जियम का सपना तोड़ा। एरलिंग हालैंड की नॉर्वो को इंग्लैंड के हाथों 1-2 की हार का सामना करना पड़ा। वहीं मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना ने 125 मिनट तक चले मुकाबले में स्विट्जरलैंड को मात दी। 15 और 16 जुलाई को दोनों सेमीफाइनल खेले जाने वाले हैं। आइए जानते हैं कि कौन सी टीम किस से भिड़ने वाली, साथ ही भारत में आप इन मैचों को कितने बजे देख पाएंगे।

फ्रांस बनाम स्पेन - 15 जुलाई

पहला सेमीफाइनल डलास में 15 जुलाई को भारतीय समयानुसार रात 12: 30 बजे खेला जाएगा। यह मुकाबला मौजूदा टूर्नामेंट की दो सबसे मजबूत यूरोपीय टीम फ्रांस और स्पेन के बीच है। फ्रांस ने नॉकआउट चरण में पैराग्वे और क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को हराकर अंतिम चार में जगह बनाई। दूसरी ओर, स्पेन ने राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल और क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को मात देकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया।

स्पेन के 18 वर्षीय स्टार लामिन यामाल ने किलीयन एम्बाप्पे को डर कर रहने की सलाह दे दी है। उन्होंने याद दिलाया कि यूरो कप में भी स्पेन की टीम फ्रांस पर भारी पड़ी थी। दूसरी ओर फ्रांस की ओर से अभी तक इसके जवाब में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बहरहाल, मैदान पर दम दिखाने वाली टीम ही फाइनल की टिकट हासिल करेगी।

अर्जेंटीना बनाम इंग्लैंड - 16 जुलाई

मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ने वाले हैं। 16 जुलाई को यह मुकाबला अटलान्टा में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार इस मैच का प्रासारण रात 12:30 बजे से शुरू हो जाएगा। इंग्लैंड ने क्वार्टर फाइनल में शानदार फॉर्म में आ रही नॉर्वे को हराकर टूर्नामेंट से बाहर किया और अंतिम 4 में जगह बनाई। इस टीम के कप्तान हैरी केन 6 गोल के साथ बेहतरीन लय में नजर आ रहे हैं।

दूसरी ओर लियोनेल मेसी क्वार्टर फाइनल में अपनी टीम की 3-1 से जीत में एक भी गोल से योगदान नहीं दे सके। हालांकि 8 गोल के साथ वे लीडिंग गोल स्कोरर खिलाड़ियों में बने हुए हैं। अर्जेंटीना बैक टू बैक दूसरी ट्रॉफी की ओर देख रही है। जबकि इंग्लैंड 1966 के बाद अपने दूसरे खिताब की तलाश में है।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भारतीय तीरंदाजी टीम को रजत पदक जीतने पर दी बधाई

अमरावती,12 जुलाई 2026।आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को मैड्रिड में आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 4 में महिला कंपाउंड टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने ज्योति सुरेखा वेन्नम, पृथिका प्रदीप और चिकिथा तानिपार्थी को बधाई दी। चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, ÷हमें आंध्र प्रदेश की बेटी ज्योति सुरेखा वेन्नम पर खास तौर पर गर्व है, जिनका इंटरनेशनल लेवल पर लगातार बेहतरीन प्रदर्शन हमारे राज्य के युवा एथलीटों को प्रेरणा देता है। अपेक्स 2036 के ज़रिए, हम उनके जैसे और भी कई चैंपियन तैयार करने के लिए कमिटेड हैं जो आंध्र प्रदेश और भारत का नाम रोशन करेंगे। टीम इंडिया को टूर्नामेंट में लगातार सफलता की शुभकामनाएं। खेल मंत्री मंडीपल्ली रामप्रसाद रेड्डी ने भी स्पेन के मैड्रिड में चल रहे आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज-4 में सिल्वर मेडल जीतने पर भारतीय महिला कंपाउंड आर्चरी टीम के सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ज्योति सुरेखा वेन्नम, पृथ्वी प्रदीप और चिकिथा तनिपार्थी ने बहुत अच्छा टैलेंट दिखाया। उन्होंने आगे कहा,ये एथलीट, जिन्होंने ग्लोबल स्टेज पर भारत का झंडा ऊंचा रखा है, सभी के लिए प्रेरणा हैं। सेमीफाइनल में साउथ कोरिया को हराकर फाइनल में पहुंचना एक शानदार उपलब्धि है। सिल्वर मेडल जीतना भारतीय तीरंदाजी टैलेंट के लिए एक और बड़ा कदम है।÷

एशियन गेम्स से पहले अनिमेष कुजूर ने 100 मीटर दौड़ में बनाया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड

वेट्जलर,12 जुलाई 2026।भारत के युवा धावक अनिमेष कुजूर ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 100 मीटर दौड़ में नया मुकाम हासिल किया है। ओडिशा के इस धावक ने प्यूमा फास्ट आर्म्स फास्ट लेग्स 2026 मीट में पुरुषों की 100 मीटर फाइनल रेस में 10.14 सेकंड का अपना सर्वश्रेष्ठ समय निकाला। अनिमेष विदेशी धरती पर 100 मीटर की रेस को सबसे तेज पूरा करने वाले भारतीय एथलीट बने हैं। इसके साथ ही वह भारत की तरफ से गुरिंदरवीर सिंह के बाद 100 मीटर की रेस को सबसे तेज पूरा करने वाले खिलाड़ी बने हैं। गुरिंदरवीर 100 मीटर की रेस को 10.09 सेकंड में पूरा कर चुके हैं और उनके नाम नेशनल रिकॉर्ड दर्ज है।अनिमेष ने प्रतियोगिता की शुरुआत भी शानदार तरीके से की थी। उन्होंने दिन में हुई 100 मीटर हीट रेस को 10.19 सेकंड के समय के साथ जीतकर फाइनल में जगह बनाई। इसके बाद फाइनल में उन्होंने अपने प्रदर्शन को और बेहतर किया और अपना पिछला व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 10.15 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ते हुए रेस को 10.14 सेकंड में पूरा किया।पुरुषों की 200 मीटर दौड़ के नेशनल रिकॉर्ड धावक अनिमेष अब भारत के सबसे तेज धावकों में शामिल हो गए हैं। भारत की ओर से 100 मीटर की रेस को सबसे कम समय में पूरा करने वाली लिस्ट में अनिमेष के तीन प्रदर्शन शामिल हैं। गुरिंदरवीर सिंह के 10.09 सेकंड के रिकॉर्ड के बाद अनिमेष का 10.14 सेकंड, 10.15 सेकंड और 10.18 सेकंड का समय शामिल है।

हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती चोटिल,प्रिंस यादव और रवि बिश्नोई की टीम इंडिया में एंट्री

मुंबई,12 जुलाई 2026। इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज और जिम्बाब्वे के खिलाफ टी 20 आई सीरीज से पहले टीम इंडिया को झटका लगा है, क्योंकि हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण बाहर हो गए हैं। पेसर प्रिंस यादव और स्पिनर रवि बिश्नोई ने इन दोनों की जगह ओडीआई और टी 20 आई टीम में जगह बनाई है। बीसीसीआई ने रविवार को एक बयान में कहा,मेन्स सिलेक्शन कमेटी ने हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती की जगह प्रिंस यादव और रवि बिश्नोई को भारत की ओडीआई और टी20आई टीम में शामिल किया है। राणा ने ट्रेंट ब्रिज में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20आई के दौरान अपने दाहिने हैमस्ट्रिंग में अचानक तकलीफ होने की बात कही थी। बाद के स्कैन में ग्रेड 1 हैमस्ट्रिंग इंजरी का पता चला। वह इंग्लैंड के खिलाफ आने वाली ओडीआई सीरीज से बाहर हो गए हैं और आगे के असेसमेंट और मैनेजमेंट के लिए बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को रिपोर्ट करेंगे। बयान में आगे कहा गया,चक्रवर्ती ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी 20आई के दौरान अपने बाएं हैमस्ट्रिंग में अचानक तकलीफ होने की भी बात कही। बाद में एमआर आई स्कैन से ग्रेड 2 हैमस्ट्रिंग चोट का पता चला। स्पेशलिस्ट मेडिकल सलाह के आधार पर, उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ आने वाली टी20आई सीरीज़ से बाहर कर दिया गया है। वह आगे के मैनेजमेंट के लिए बीसीसीआई सीओई को रिपोर्ट करेंगे। इंग्लैंड ओडीआई के लिए भारत की अपडेटेड टीमः शुभमन गिल (कप्तान),रोहित शर्मा,विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान),केएल राहुल (विकेट कीपर),ईशान किशन (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा,अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार, प्रिंस यादव ज़िम्बाब्वे टी20आई के लिए भारत की अपडेटेड टीमः श्रेयस अय्यर (कप्तान),वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उप-कप्तान),ईशान किशन (विकेट कीपर),शिवम दुबे,सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, प्रिंस यादव,यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव,प्रभसिमरन सिंह (विकेट कीपर),रवि बिश्नोई इंग्लैंड से पांच मैचों की टी20आई सीरीज़ 0-4 से हारने के बाद, मेन इन ब्लू 14 जुलाई से शुरू होने वाली तीन मैचों की ओडीआई सीरीज़ में नई नंबर 1 टी20आई टीम से भिड़ेगा।

वरिष्ठता पर हाईकोर्ट की आपत्ति

फिर भी रिव्यू में गई सरकार!

योग्यता पर भी उठे सवाल

हाईकोर्ट ने वरिष्ठता सूची पर उठाए सवाल

आखिर किसे बचाने की कोशिश?

फूड सेफ्टी ऑफिसरों की वरिष्ठता पर घमासान,हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं थमा विवाद

हाईकोर्ट ने कहा...2015 और 2016 की नियुक्ति अलग,फिर भी सरकार ने रिव्यू का रास्ता क्यों चुना?

हाईकोर्ट ने निरस्त किया विभागीय आदेश,फिर भी रिव्यू में गई सरकार...आखिर क्या है वजह?

वरिष्ठता विवाद से आगे बढ़ा मामला,अब शैक्षणिक योग्यता पर भी उठे गंभीर सवाल

सर्वेश-सिद्धार्थ की वरिष्ठता पर हाईकोर्ट की आपत्ति,अब पात्रता पर भी जांच की मांग तेज

पहले वरिष्ठता या पहले पात्रता की जांच? फूड सेफ्टी ऑफिसरों के विवाद ने खड़े किए बड़े सवाल

वरिष्ठता, पदोन्नति और शैक्षणिक योग्यता...फूड सेफ्टी विभाग का विवाद गहराया

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं थमा विवाद, वरिष्ठता के साथ अब डिग्री पर भी सवाल

क्या नियमों से ऊपर है विभागीय बचाव? वरिष्ठता विवाद के बीच शैक्षणिक योग्यता की जांच की मांग...

हाईकोर्ट ने खारिज की वरिष्ठता की दलील, फिर भी रिव्यू में सरकार...अब सर्वेश-सिद्धार्थ की पात्रता पर भी उठे सवाल

2015 और 2016 की अलग नियुक्ति को एक करने पर हाईकोर्ट ने जताई आपत्ति,नियुक्ति में प्रयुक्त शैक्षणिक योग्यता की जांच की मांग के बीच शासन के फैसले पर उठ रहे प्रश्न

रवि सिंह

रायपुर/बिलासपुर,12 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में फूड सेफ्टी ऑफिसरों की वरिष्ठता को लेकर वर्षों से चल रहा विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है,छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वर्ष 2015 और वर्ष 2016 की अलग-अलग भर्ती प्रक्रियाओं से नियुक्त अधिकारियों को एक ही वरिष्ठता सूची में शामिल करना सेवा नियमों के अनुरूप नहीं है, न्यायालय ने विभाग द्वारा जारी वरिष्ठता सूची के आधार बने आदेश को निरस्त करते हुए पूरे मामले पर पुनर्विचार का निर्देश दिया था,लेकिन अब राज्य शासन ने उस आदेश को लागू करने के बजाय उसके खिलाफ पुनर्विलोकन (रिव्यू) याचिका दायर करने का निर्णय लिया है।

क्या है पूरा मामला?-विवाद वर्ष 2021 में जारी फूड सेफ्टी ऑफिसरों की वरिष्ठता (ग्रेडेशन) सूची से जुड़ा है,इस सूची में वर्ष 2015 में नियुक्त कुछ अधिकारियों को वर्ष 2016 में नियुक्त अधिकारियों से नीचे स्थान दिया गया था। इसी को चुनौती देते हुए अपर्णा आर्या,राखी ठाकुर और सरिता पटेल ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी,याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनकी नियुक्ति दिसंबर 2015 में हुई थी,जबकि सर्वेश कुमार यादव,सिद्धार्थ पांडे और एक अन्य अधिकारी की नियुक्ति मार्च 2016 में हुई,इसके बावजूद विभाग ने वरिष्ठता सूची में वर्ष 2016 में नियुक्त अधिकारियों को उनसे ऊपर स्थान दे दिया,जिससे उनकी पदोन्नति और अन्य सेवा लाभ प्रभावित हो रहे हैं।

वरिष्ठता ही तय करती है पदोन्नति का भविष्य-सरकारी सेवाओं में वरिष्ठता केवल सूची तक सीमित नहीं होती, उसी के आधार पर पदोन्नति,चयन वेतनमान, विभागीय पदस्थापन और भविष्य के कई प्रशासनिक निर्णय लिए जाते हैं,यदि बाद में नियुक्त अधिकारी को वरिष्ठता में ऊपर रखा जाता है तो पहले नियुक्त कर्मचारियों के संवैधानिक और सेवा संबंधी अधिकार प्रभावित होते हैं, यही कारण था कि इस मामले में वरिष्ठता सूची को लेकर विवाद सीधे पदोन्नति से जुड़ गया।

आदेश लागू करने के बजाय सरकार पहुंची रिव्यू में-हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उम्मीद थी कि विभाग न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए वरिष्ठता सूची पर पुनर्विचार करेगा,लेकिन 10 जुलाई 2026 को विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने महाधिवक्ता कार्यालय को पत्र जारी कर स्पष्ट कर दिया कि राज्य शासन ने 28 अप्रैल 2026 के आदेश के खिलाफ पुनर्विलोकन (रिव्यू) याचिका दायर करने का निर्णय लिया है,महाधिवक्ता कार्यालय को समय-सीमा के भीतर रिव्यू पिटीशन दाखिल करने तथा कार्रवाई से विभाग को अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही स्वास्थ्य विभाग को भी आवश्यक समन्वय करने के लिए पत्र भेजा गया है।

रिव्यू के फैसले पर टिकी विभाग की निगाहें-अब यह पूरा मामला एक बार फिर न्यायालय के समक्ष जाएगा,रिव्यू पिटीशन पर आने वाला निर्णय केवल तीन याचिकाकर्ताओं या संबंधित अधिकारियों तक सीमित नहीं रहेगा,बल्कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में वरिष्ठता निर्धारण,पदोन्नति और भविष्य की सेवा संबंधी व्यवस्थाओं पर भी व्यापक प्रभाव डाल सकता है, फिलहाल इतना स्पष्ट है कि हाईकोर्ट ने अलग-अलग भर्ती वर्षों को मिलाकर वरिष्ठता तय करने की प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं,जबकि राज्य शासन उस आदेश की न्यायिक समीक्षा चाहता है, अब अंतिम निर्णय न्यायालय के रिव्यू आदेश पर निर्भर करेगा।

वरिष्ठता से पहले शैक्षणिक योग्यता की जांच क्यों नहीं?- फूड सेफ्टी ऑफिसर पद पर सर्वेश कुमार यादव और सिद्धार्थ पांडे के नाम केवल वरिष्ठता और पदोन्नति विवाद तक सीमित नहीं हैं,इन दोनों अधिकारियों की शैक्षणिक योग्यता और नियुक्ति की पात्रता को लेकर भी लंबे समय से शिकायतें विभिन्न स्तरों पर की जाती रही हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री,मुख्य सचिव,स्वास्थ्य विभाग, एफएसएसएआई,ईओडब्ल्यू और एसीबी सहित कई संस्थाओं को भेजे गए शिकायत-पत्र में भी मांग की गई है कि फूड सेफ्टी ऑफिसरों की नियुक्ति और पदोन्नति में प्रयुक्त शैक्षणिक योग्यता,डिग्री की वैधता तथा एफएसएसएआई नियमों के अनुरूप पात्रता की स्वतंत्र जांच कराई जाए, ऐसे में विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब संबंधित अधिकारियों की मूल पात्रता और शैक्षणिक दस्तावेजों पर ही शिकायतें लंबित हैं, तब उनकी वरिष्ठता और पदोन्नति का बचाव करने की इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है? प्रशासन पहले यह स्पष्ट क्यों नहीं करता कि जिन अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ मिला,वे नियुक्ति के समय निर्धारित योग्यता और पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते थे या नहीं? कई शिकायतकर्ताओं का तर्क है कि यदि किसी अधिकारी की नियुक्ति की वैधता या शैक्षणिक योग्यता ही जांच के दायरे में है,तो उस स्थिति में उसकी पदोन्नति का प्रश्न स्वाभाविक रूप से द्वितीयक हो जाता है,पहले यह तय होना चाहिए कि संबंधित अधिकारी की नियुक्ति विधिसम्मत थी या नहीं,यदि नियुक्ति ही नियमों के अनुरूप नहीं पाई जाती, तो उसके आधार पर दी गई पदोन्नति और वरिष्ठता भी स्वतः विवाद के घेरे में आ सकती है, शिकायतों में यह भी मांग की गई है कि वर्ष 2011 से अब तक फूड सेफ्टी ऑफिसर पद पर हुई सभी नियुक्तियों और पदोन्नतियों की स्वतंत्र जांच कराई जाए, सभी अधिकारियों की शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन कराया जाए तथा जांच पूरी होने तक प्रस्तावित पदोन्नतियों पर भी विचार रोका जाए, हालांकि,यह भी उल्लेखनीय है कि अब तक किसी सक्षम जांच एजेंसी या न्यायालय ने सर्वेश कुमार यादव अथवा सिद्धार्थ पांडे की शैक्षणिक योग्यता या नियुक्ति को अवैध घोषित नहीं किया है, वर्तमान में ये आरोप शिकायतों और जांच की मांग के रूप में हैं, संबंधित अधिकारियों और विभाग का विस्तृत पक्ष सामने आना तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच पूरी होना अभी शेष है।

विभाग ने मेरिट सूची का दिया था आधार...

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में यह तर्क दिया गया कि वरिष्ठता सूची छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सामान्य सेवा शर्तें) नियम, 1961 के नियम-12 के अनुसार तैयार की गई है,विभाग का कहना था कि चूंकि सर्वेश कुमार यादव और सिद्धार्थ पांडे चयन की मेरिट सूची में ऊपर थे,इसलिए उन्हें वरिष्ठता सूची में भी ऊपर रखा गया, इसी आधार पर विभाग ने न्यायालय से याचिका खारिज करने की मांग की।

हाईकोर्ट ने माना–दो अलग नियुक्तियां प्रक्रियाओं को नहीं जोड़ा जा सकता

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2015 और वर्ष 2016 की अलग-अलग नियुक्तियां प्रक्रिया का परिणाम थीं,ऐसे में दोनों वर्षों के अधिकारियों को एक ही संयुक्त वरिष्ठता सूची में रखना नियम-12 की भावना के विपरीत है, न्यायालय ने कहा कि जब भर्ती वर्ष अलग हैं,तो वरिष्ठता निर्धारण भी उसी आधार पर होना चाहिए,अदालत ने 18 नवंबर 2021 के विभागीय आदेश को निरस्त करते हुए संबंधित प्राधिकारी को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता पर नए सिरे से विचार किया जाए और 60 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाए।

क्या उठ रहे हैं सवाल?

सरकार के इस फैसले के बाद विभागीय हलकों में कई सवाल चर्चा का विषय बने हुए हैं,सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब हाईकोर्ट ने अलग-अलग भर्ती वर्षों की संयुक्त वरिष्ठता सूची पर स्पष्ट आपत्ति जताते हुए पुनर्विचार का निर्देश दिया था,तब विभाग ने पहले न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के बजाय रिव्यू याचिका का रास्ता क्यों चुना? दूसरा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या सरकार विभाग द्वारा पूर्व में जारी वरिष्ठता सूची का विधिक बचाव कर रही है, या उसके पास ऐसे अतिरिक्त कानूनी आधार हैं जिन्हें वह अब रिव्यू याचिका में न्यायालय के समक्ष रखना चाहती है? इन प्रश्नों का उत्तर फिलहाल शासन की रिव्यू याचिका और उसके तर्क सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा।

सरकार का पक्ष जानना भी जरूरी

यह उल्लेखनीय है कि उपलब्ध सरकारी पत्र में केवल रिव्यू पिटीशन दायर करने के निर्णय का उल्लेख है, उसमें यह नहीं बताया गया है कि राज्य शासन किन विशिष्ट कानूनी आधारों पर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दे रहा है,इसलिए यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि किसी विशेष अधिकारी को नियमों के विपरीत लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में सरकार का विस्तृत पक्ष अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है।

रिव्यू पिटीशन पर टिकी सबकी नजर...

अब पूरा मामला पुनः हाईकोर्ट के समक्ष जाएगा। रिव्यू पिटीशन पर आने वाला फैसला केवल कुछ अधिकारियों की वरिष्ठता तक सीमित नहीं रहेगा,बल्कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में भविष्य की वरिष्ठता सूची,पदोन्नति प्रक्रिया और सेवा नियमों की व्याख्या पर भी व्यापक प्रभाव डालेगा, इसके साथ ही यदि शैक्षणिक योग्यता और पात्रता संबंधी शिकायतों की स्वतंत्र जांच होती है, तो उसका प्रभाव भी इस पूरे विवाद की दिशा तय कर सकता है।

नक्सल मुक्त गांवों में 15 अगस्त को निकलेगी तिरंगा यात्रा प्रत्येक गांव को मिलेगी 1-1 करोड़ की विकास राशि

रायपुर,12 जुलाई 2026। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। अब नक्सल मुक्त हुए गांवों में 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकलेगी और प्रत्येक गांव को विकास के लिए 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा जेल में बंद पूर्व नक्सलियों की रिहाई के लिए विधिसम्मत समीक्षा की जाएगी। इसके लिए विधि विभाग की सहायता से अभियोजन अधिकारियों और शासकीय वकीलों की टीम बनाई जाएगी तथा प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में होगी।

तिरंगा यात्रा : 15 अगस्त को सभी नक्सल मुक्त गांवों में तिरंगा यात्रा और ध्वजारोहण होगा। उद्देश्य - राष्ट्रीय एकता और जनभागीदारी का संदेश।

विकास राशि : पूर्व के अति नक्सल प्रभावित और अब नक्सल मुक्त गांवों के लिए प्रत्येक गांव को 1-1 करोड़ रुपये। प्रथम चरण में सुकमा 20, बीजापुर 20 और नारायणपुर 10 गांव यानी कुल 50 गांवों का चयन।

आवास : नक्सल पीड़ित एवं पुनर्वासित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के विशेष प्रावधानों के तहत घर।

स्मारक : नक्सली हिंसा से प्रभावित प्रमुख स्थानों पर सामुदायिक स्मारक बनेंगे।

सहायता : शहीद जवानों और मृत नागरिकों के परिजनों को शासन की सभी सहायता समय पर मिलेगी।

जेल में बंद पूर्व नक्सलियों पर क्या कहा: विजय शर्मा ने कहा कि जिन नक्सल मामलों में जनहानि नहीं हुई है,उनमें जेल में निरुद्ध आरोपियों के प्रकरणों की विधिसम्मत समीक्षा कर रिहाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। इसके लिए विधि विभाग की मदद से अभियोजन अधिकारियों और शासकीय वकीलों की टीम बनेगी,प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में होगी।

शहीद रजनीकांत सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि डीजीपी अरुण देव गौतम ने परिवार से की मुलाकात

भिलाई,12 जुलाई 2026। राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा नक्सली हमले में शहीद हुए रिसाली (भिलाई) निवासी वीर जवान रजनीकांत सिंह की 17वीं पुण्यतिथि पर रविवार को उनके स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। प्रेम संगवारी बहुउद्देशीय सेवा समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अरुण देव गौतम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। डीजीपी अरुण देव गौतम ने शहीद रजनीकांत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके अदम्य साहस तथा सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि शहीदों का त्याग देश की अमूल्य धरोहर है और उनके परिवारों के प्रति समाज व पुलिस विभाग का दायित्व सदैव बना रहेगा। कार्यक्रम में दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अभिषेक शांडिल्य, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर, नेवई थाना प्रभारी अनिल साहू सहित पुलिस विभाग के अनेक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान डीजीपी ने शहीद की पत्नी पिंकी साहू एवं अन्य परिजनों से आत्मीय मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि भविष्य में किसी भी आवश्यकता की स्थिति में पूरा पुलिस परिवार उनके साथ खड़ा रहेगा। समारोह को संबोधित करते हुए प्रेम संगवारी बहुउद्देशीय सेवा समिति के संयोजक विष्णु पाठक ने वर्ष 2009 के मदनवाड़ा नक्सली हमले का स्मरण करते हुए शहीद रजनीकांत सिंह के अद्वितीय बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि शहीदों का सम्मान केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि समाज का नैतिक दायित्व है। उनके साहस और राष्ट्रभक्ति से नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती रहेगी। विष्णु पाठक ने बताया कि समिति प्रत्येक वर्ष शहीदों की स्मृति को जीवंत बनाए रखने तथा उनके परिवारों के सम्मान के उद्देश्य से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित करती है, ताकि समाज उनके सर्वोच्च बलिदान को सदैव याद रखे।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)